

अनिवार्य प्रश्न

वर्ष 03, अंक 07, जुलाई, 2021, पृष्ठ: 8, : सहयोग मूल्य : 11 रुपये

अगर पढ़िए तो सिर्फ सच पढ़िए!



पाप का पर्दाफाश... 2

पत्रकारिता के शाहीदों को नमन... 5

वालीवुड में यौन अपराध... 8

हाय रे सरकार, पेट्रोल सौ के पार

देश में पहली बार 9 राज्यों की जनता 100 रुपये प्रति लीटर

का पेट्रोल खरीदने को मजबूर हो गयी है। सरकार फिर भी बेरहमी कर रही है।

अनिवार्य प्रश्न, विशेष प्रतिनिधि। देश के लगभग 148 से 150 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार हो गई है। आम आदमी को महंगाई डायन सही में खाए जा रही है। विगत महीनों में पेट्रोल-डीजल 10 रुपये से ज्यादा प्रति लीटर महंगा हो चुका है, सरकार द्वारा पिछले दिनों पचीसों बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाये जा चुके हैं। इतिहास में पहली बार पेट्रोल 100 रुपये से अधिक महंगा हो चुका है। तेल की महंगाई से आम आदमी निरन्तर परेशान हो रहा है। इसका असर मालदुलाई बढ़ने से सभी वस्तुओं की कीमतों पर हो रहा है। तेल का जो भाव

है ये नागरिकों और ग्राहकों को दिक्कत दे रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। अनिवार्य प्रश्न यह है कि टैक्स लादकर महंगाई लाने वाली सरकार के पास महंगाई कम का कोई उपाय क्यों नहीं है? या वह महंगाई घटाने की इच्छा क्यों नहीं कर पा रही है?

पेट्रोल 100 रुपये से ऊंची कीमत पर आ गया है

देश में पहली बार 9 राज्यों की जनता 100 रुपये प्रति लीटर का पेट्रोल खरीदने को मजबूर हो गयी है। सरकार फिर भी बेरहमी कर रही है। जनता वैसे ही आर्थिक सुस्ती व बेरोजगारी से

कराह रही है। ऐसे में पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतें समाज में सौम्य वातावरण को खत्म कर सकती हैं।

देश के जिन 9 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल का फुटकर दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और लद्दाख जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्या अच्छी खासी है। जिन्हें इस बोझ को उठाना है। पिछले दिनों की कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल भी 100 रुपये

प्रति लीटर के ऊपर जा चुका था। और यहां पेट्रोल की कीमत बढ़कर 107.53 रुपये प्रति लीटर तक हो गई थी।

तेल पर सरकारी टैक्स अधिक होने से राजस्व की भारी कमाई

सिर्फ पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच ही 2 लाख 35 हजार करोड़ रुपया जनता की जेब से निकलकर केंद्र सरकार के खजाने में राजस्व के रूप में जा चुका है। पाठकों को जानना चाहिए कि पेट्रोल-डीजल की कीमत एक साल में

लगभग 25 रुपये तक बढ़ चुकी है। ये सारा बोझ देश के नागरिक ढो रहे हैं। सरकारें जब-जब अपने कोल्हू की चकरी व शोभा गुच्छियाँ बढ़ती हैं आम आदमी और अधिक दबकर पिसने लगता है। उसका सपना उसके खून के साथ बह जाता है।

देश	रु./प्र.ली.
वेनेजुएला	1.48
ईरान	4.82
अंगोला	18.48
अल्जीरिया	25.45
कुवैत	25.85
नाइजीरिया	30.29
तुर्कमेनिस्तान	31.74
कजाखस्तान	32.93
इथियोपिया	36.53
मलेशिया	36.63
इराक	38.16
कतर	38.69
मिस्र	41.42



गरीब व मध्यम वर्ग को लग रहा बड़ा झटका

महंगे परिवहन से

और बड़ी महंगाई

विश्व एक नजर में

दुनिया भर में पेट्रोल की औसत कीमत 1.17 अमेरिकी डॉलर प्रति लीटर है। एक सामान्य नियम के रूप में, अमीर देशों की कीमतें अधिक होती हैं जबकि गरीब देशों और तेल का उत्पादन व निर्यात करने वाले देशों में कीमतें काफी कम होती हैं। विभिन्न देशों में कीमतों में अंतर मुख्य रूप से गैसोलीन के लिए विभिन्न करों और सब्सिडी के कारण है। सभी देशों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में समान पेट्रोलियम कीमतों तक पहुंच है लेकिन फिर अलग-अलग कर लगाने का फैसला करते हैं। सूचीबद्ध 167 देशों/क्षेत्रों में से 57 की कीमत 1 अमेरिकी डॉलर से कम है। सत्तर के पास 1.00 डॉलर से 1.50 डॉलर, 35 के बीच 1.50 डॉलर - 2.00 डॉलर, और चार के पास 2 डॉलर से अधिक है। कीमतें 21 जून 2021 की तारीख के अनुसार बताई जा रही हैं। वेनेजुएला की कीमत सबसे सस्ती है, यहां केवल 0.02 डॉलर प्रति लीटर, इसके बाद ईरान (0.06 डॉलर) का स्थान है। शीर्ष दस सबसे सस्ते देशों में, पांच देश एशिया में, चार अफ्रीका में और एक दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। हांगकांग में सबसे महंगी कीमत 2.50 डॉलर है, इसके बाद नोदरलैंड और नॉर्वे हैं।

वायरल सच

मुख्तार से जुड़े चर्चित एंबुलेंस प्रकरण में एआरटीओ राजेश्वर यादव निलंबित



अनिवार्य प्रश्न, संवाद। बलिया। देश प्रसिद्ध व चर्चित बहुजन समाज पार्टी के विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पर लगातार गाज गिरती जा रही है। मुख्तार से जुड़े एक चर्चित एंबुलेंस प्रकरण में बलिया में दो साल से कार्यरत रहे एआरटीओ राजेश्वर यादव को निलंबित कर दिया गया है। शासन द्वारा अंसारी के एंबुलेंस प्रकरण में एआरटीओ राजेश्वर यादव को दोषी पाये जाने के कारण निलंबित किया गया और उन्हें मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि जनपद बाराबंकी में जिस समय मुख्तार से जुड़ी एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय राजेश्वर बाराबंकी में ही तैनात थे। एआरटीओ राजेश्वर यादव पर की गई इस निलंबन की कार्यवाही से बलिया में परिवहन विभाग के अधिकारियों में दहसत का माहौल व्याप्त हो गया है। हालांकि आगे

की जांच में बाराबंकी के कई लोगों के फंसने की संभावना साफ-साफ दिख रही है। जिससे कि पूरे एआरटीओ दफ्तर में हड़कंप मचा हुआ है। नाम न प्रकाशित करने का निवेदन करते हुए एआरटीओ दफ्तर के पास एक दुकान चलाने वाले ने अनिवार्य प्रश्न प्रतिनिधि से बताया है कि सभी कर्मचारी इस समय सभी को पत्रकार ही समझ रहे हैं और किसी से बात करने से भाग रहे हैं। उसने आगे कहा कि यहां भ्रष्टाचार तो होता रहा है लेकिन बलिया में कार्यरत एआरटीओ की छवि अब तक साफ रही थी। लेकिन इस घटना से यह भी साफ हो गया है कि वह मुख्तार अंसारी के अप्रत्यक्ष सहयोगी रहे हैं। हालांकि और कितनों की नौकरी जाएगी अभी कहा नहीं जा सकता। बाराबंकी में और भी कई परिवहन कर्मियों का जुड़ाव इस प्रकरण से हो सकता है और इसकी जांच शासन द्वारा की जा रही है।

डाइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ दफ्तर में नहीं देनी होगी परीक्षा

ट्रेनिंग केंद्रों पर सफलतापूर्वक

परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों

को डाइविंग लाइसेंस के लिए

आवेदन करते समय डाइविंग

टेस्ट की आवश्यकता से मिलेगी छूट

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 01 जुलाई, 2021

से लागू होंगे। ऐसे केंद्रों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवारों को उच्च

अब मोटर ट्रेनिंग सेन्टर की परीक्षा पास कर लेने पर मानी जायेगी पात्रता

गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर और खास डाइविंग टेस्ट ट्रैक से युक्त होगा। इन केंद्रों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार उपचारात्मक और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का लाभ उठाया जा सकता है।

साथ ही इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को डाइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन

करते समय डाइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट मिलेगी। वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा डाइविंग टेस्ट लिया जाता है। डाइवरों को ऐसे मान्यता प्राप्त डाइविंग प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद डाइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इन केंद्रों को उद्योगों की जरूरत के अनुसार विशिष्ट प्रशिक्षण भी प्रदान करने की अनुमति है।



सरकार का कहना है कि कुशल डाइवरों की कमी भारतीय सड़क क्षेत्र में प्रमुख समस्याओं में से एक है। सड़क नियमों के ज्ञान की कमी के कारण बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 8 केंद्र सरकार को चालक प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है।

हालात से सत्ता की विफलताओं के लिए



बनारस में शव जलाने के लिए घाट सुधार के साथ श्मशान की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था इस ओर संकेत करती है कि हम अपने यहां जीवन को संरक्षित नहीं कर पाए। विगत दिनों नगर निगम ने एक सूचना में साफ तौर पर बताया था कि हम आम लोगों को होने वाले कष्ट को कम करने के लिए शवदाह के वैकल्पिक स्थलों की व्यवस्था कर रहे हैं।

लेकिन यहां पर अनिवार्य प्रश्न यह उठता है कि इतने शव क्यों? कैसे? जीवन जीने के

लिए उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था व इसके सामयिक पड़ने वाली आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक आवश्यक आकस्मिक चिकित्सा सुविधा की तैयारी क्यों नहीं की गई? काशी ही नहीं पूरे देश से आई सूचना के मुताबिक किसी अस्पताल में ऑक्सीजन घट गया, कहीं कोई औषधि घट गई, कहीं कहीं वेड घट गया तो कहीं डॉक्टर ही एडमिट लेने के लिए तैयार नहीं थे।

कुल मिलाकर मुगल काल हो या अंग्रेजों का शासन आम आदमी अपने चिकित्सा व शिक्षा को लेकर भगवान पर ही

निर्भर रह गया। अब आज भी हाशिए पर है। ऐसे मोड़ पर अब सवाल यह उठाना जरूरी हो जाता है कि क्या हमारे बनाए गए संविधान में दोष है? हमारे चुनावों में दोष है? हमारी तैयारियों में दोष है? आखिर इतनी मौतों के लिए हम तैयार क्यों नहीं हैं? चलते फिरते तमाम बातों पर जुर्माना करने वाली सरकारें क्या स्वयं पर या पिछली सरकारों पर जुर्माना लगा सकती हैं?

आज तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए, आज तक हम अपनी आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था को

ठीक नहीं कर पाए, आज तक अस्पताल नहीं बना पाए। सरकारी आकड़े कुछ भी बोलते हैं जितनी जरूरत समुदायों को होती है उस की अपेक्षा एक प्रतिशत ही अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में 70 साल की तरक्की और उन्नति के बाद समाज ने अपने लिए क्या कुछ बना पाया है? यह चिंतन का विषय है। अस्पतालों के बाहर मरीज मर रहे थे, उनका दाखिला तक नहीं हो पा रहा था, चिकित्सक जो सेवा भाव से काम कर रहे थे वह भी बीमार पड़ रहे थे, भ्रष्टाचारी और गैर जिम्मेदार चिकित्सक

जुर्माने भरता समाज

अपना पल्ला झाड़ ले रहे थे, कुछ अस्पताल इस आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं। चिकित्सकीय सामग्रियों सेवाओं की बेहिसाब कीमत वसूल रहे हैं।

बाजार का यह चेहरा यह समाज समझ नहीं पा रहा है। मौतों की भी सौदेबाजी हो रही है। चारों तरफ चीखें हैं। उन्नति अगर यही है तो हमारी पहले वाली शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था ज्यादा ठीक थी। जहां भावनाएं अधिक थीं बिक्री के सामान कम थे। समाज को फिर से

लौटना होगा, अपने उसी पिछड़ेपन की ओर जहां आबादी कम थी उसके सापेक्ष चिकित्सा व सुरक्षा की भावनात्मक व उत्तम व्यवस्था थी। साथ ही इस हाहाकार से निकलना होगा और अपने शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता के साथ नैतिक शिक्षा को जोड़ना होगा।

समाज को समाज रहने देना होगा। इसे बाजार से दूर करना होगा। बाजार के चलन को गौण चलन मानना होगा। साथ ही चुनावों में सही नेतृत्व के लिए सामूहिक प्रयत्न करना होगा। दूसरा समाधान नहीं है।

वैतनिक पदों पर संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि बनने के लिए संपर्क करें - 916 1099088

मर रही है सच्चाई खड़ा करना ही होगा- अनिवार्य प्रश्न

हर कलम विकती नहीं।

www.anivaryaprashna.in

पुण्य नगरी काशी में एक बार फिर पाप का पर्दाफाश

जगतगंज स्थित कैलगढ़ कॉलोनी में एक किराए के मकान में किया जा रहा था देह व्यापार



अनिवार्य प्रश्न, ब्यूरो संवाद। वाराणसी। काशी जैसे तो अपने धर्म और पवित्रता के लिए जानी जाती है लेकिन स्थानीय पुलिस ने एक नए रैकेट का खुलासा किया है जो देह व्यापार से जुड़ा हुआ था। वाराणसी के पाँच इलाकों में से एक जगतगंज की एक कॉलोनी में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि सेक्स का पूरा सोदा फोन पर ही किया जाता था। और फोन पर ही लड़कियों को बुलाया जाता था।

सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तार की गई लड़कियों में से एक प्रयागराज की और दो वाराणसी शहर की थीं। साथ ही जो युवक पुलिस के गिरफ्त में आए हैं



उनमें शिवपुर क्षेत्र के निवासी सोनू पटेल नामक लड़के के साथ में चोलापुर का अतुल सिंह और राजेश सिंह नाम का एक और आदमी सोनिया का है। चेतगंज के पुलिस उपायुक्त ने बताया है की जगतगंज स्थित कैलगढ़ कॉलोनी में एक किराए के मकान में यह देह व्यापार किया जा रहा था। यहां के लोगों की कुछ दिनों से आ रही शिकायत और समाज की बुराई के मद्देनजर की गई पुलिस की कार्यवाही में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ।

हालांकि पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस रैकेट से मकान मालिक का कोई संबंध नहीं था। लॉकडाउन जैसे समय में

जब किसी भी मकान में लोगों का आना जाना सिमित है, वहां अपरिचितों का आना जाना हुआ तो मकान मालिक द्वारा भांपा कैसे नहीं जा सका। चल रहे रैकेट में मकान मालिक संलिप्त नहीं था यह बात थोड़ी संदिग्ध है। पूरा मामला मकान मालिक को लेकर संदिग्ध इसलिए भी है क्योंकि सेक्स रैकेट मकान के प्रथम तल पर ही किराए पर चलाया जा रहा था। हालांकि पुलिस की छापेमारी में मौके से गिरफ्तार की गई युवक-युवतियों के अलावा कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा संबंधितों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

एक विधायक पर गांधीवादी संगठन के निर्वाचन में भ्रष्टाचार व बाहुबल प्रयोग करने का आरोप

अनिवार्य प्रश्न, ब्यूरो संवाद। वाराणसी। चन्दौली के एक बाहुबली विधायक पर गांधीजी की एक संस्था पर कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है। यह आरोप उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि के बोर्ड के सदस्यों ने लगाया है। उनके अनुसार 30 जून 2021 को खादी ग्रामोद्योग आयोग तेलियाबाग वाराणसी के प्रबन्ध समिति के चुनाव में सैयदराजा चंदौली के बाहुबली विधायक स्वयं अपने गुर्गों के साथ पहुंचे थे। और बनारस में खादी ग्रामोद्योग आयोग तेलियाबाग में धमकी देते हुए पूरे समय मौजूद रहे। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि के बोर्ड के सदस्यों को अपने अध्यक्ष का चुनाव करना था। विगत समय अजय शेखर और आशा नामक दो उम्मीदवारों ने पंचा दखिल किया था। संस्था के

वर्तमान पदाधिकारियों का आरोप है कि सत्ताधारी विधायक बोर्ड के मेम्बरों सहित प्रशासन को धमकी दे कर एवं निर्णायकों को दबाव में लेकर एक पक्षीय घोषणा करवा दिये।

संस्था की नियमावली के विपरीत व कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जा कर यह घोषणा की गई। और एक विशेष पक्ष के साथ भ्रष्ट प्रशासन भी खड़ा हो गया। घटना में आरोप के अनुसार सारे नियमों के विपरीत जा कर प्रत्याशी शेखर का पंचा बिना उनकी बात कहने का अवसर दिए खारिज कर दिया गया। प्राविधान के विपरीत जल्दबाजी में दोपहर के तीन बजे ही दूसरी उम्मीदवार आशा को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। जबकि घोषित तौर पर चुनाव का परिणाम शाम पांच बजे से पहले घोषित नहीं होना चाहिए था।

सर्व सेवा संघ राजघाट में इस जबरदस्ती के खिलाफ गांधीवादी जनों और संस्था के हितैषी नागरिक संगठनों की एक मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि सरकार और प्रशासन के साथ गाँधीविचार की संस्थाओं के खिलाफ बाहुबल के इस प्रयोग और दखलंदाजी के विरुद्ध सत्याग्रह किया जाएगा। साथ ही अदालत में भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संगठनों की उक्त बैठक में विनय राय, संजीव सिंह, जागृति राही, अरविंद अंजुम, रामधीरज, अजय शेखर, शुभा, डॉ अनुप श्रमिक एवं धनन्जय राय आदि शामिल रहे। संगठन से जुड़े व असंतुष्ट गुट के रामधीरज ने अनिवार्य प्रश्न संवाददाता से उक्त आरोपों की पुष्टि की है। खबर लिखे जाने तक संबंधित विधायक की प्रतिक्रिया नहीं आ सकी थी।

वाराणसी पर्यटन गिल्ड की वेब साइट लांच

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। वाराणसी। आज दिनांक 29 जून 2021 को वाराणसी टूरिज्म गिल्ड का 21वा वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में 21 पौधों का रोपण किया गया और संकल्प लिया गया की सभी को पौधा रोपण के लिए प्रेरित किया जायेगा। वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें वाराणसी टूरिज्म गिल्ड की वेबसाइट www.varanasitourismgild.com का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ई एम नजीब रहे। विशिष्ट अतिथि कवलेश कुमार रहे। वरिष्ठ सदस्य सोनाल्ड नाडर ने संस्था की स्थापना और उद्देश्य के साथ अभी तक के कार्यों को विस्तार

से बताया तथा गिल्ड के संरक्षक उपेन्द्र गुप्ता जी ने वाराणसी और आस पास के स्थलों को अपने प्रोग्राम में जोड़ने पर बल दिया। इंडिया टूरिज्म से अमित गुप्ता तथा उत्तर प्रदेश टूरिज्म से कीर्तिमान श्रीवास्तव ने आने वाली आगामी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। अध्यक्ष सदीप पटियाल ने वित्त मंत्री के द्वारा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आसान लोन के कदम की सराहना की और आगे इस पर और भी मदद देने पर जोर दिया।

संस्था के पूर्व अध्यक्ष राशिद खान ने सरकार से मांग किया कि जिस प्रकार थोड़ा ही सही टूरिज्म इंडस्ट्री को सरकार द्वारा सहायता दी गई



है ठीक उसी प्रकार होटल इंडस्ट्री को भी सहायता दी जाए। सदस्य प्रवीण मेहता ने सरकार से अपील की कि टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े गरीब तबके जैसे कि झड़वर एवं छोटे मझोले उद्योग से जुड़े पेशेवरों की भी मदद की जानी चाहिए ताकि इस बुरे वक्त में उनको भी कुछ सहायता मिल सके। स्थापना दिवस के अवसर पर अनेक लोगों द्वारा वाराणसी टूरिज्म गिल्ड की सदस्यता ली गई। उक्त वेबिनर का संचालन

अब वाराणसी भी होगा सोलर सिटी वाला शहर

काशी को सोलर सिटी बनाने की मुहिम, अस्सी पर शाम को फ्लोटिंग सोलर प्रदर्शनी का यूपीनेडा के जिला परियोजना अधिकारी ने किया उद्घाटन

अप्र ब्यूरो, वाराणसी। सामाजिक संस्था क्लाइमेट एजेंडा ने सूरज से समृद्धि अभियान का किया आगाज अभियान में अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर व प्रयागराज को 2024 तक सोलर सिटी बनाने की तैयारी है। क्लाइमेट एजेंडा

अब नगर निगम वाराणसी में जारी होगा टिन की जगह QR CODE का प्लास्टिक कोडेड लाइसेंस

अप्र ब्यूरो, वाराणसी। नगर निगम वाराणसी के अनुज्ञप्ति विभाग द्वारा वाराणसी में पहली बार रिक्शा, ट्राली, ठेला, ठेली एवं विभिन्न प्रकार की नावों को प्रतिबंध जारी की जाने वाली लाइसेंस कंप्यूटराइज्ड QR CODE के माध्यम से जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। निगम प्रशासन के अनुसार यह नगर निगम वाराणसी के लिए एक बड़ी सफलता है। उल्लेखनीय है कि जारी की जा रही QR CODE लाइसेंस में लाइसेंस धारक का लाइसेंस नंबर, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जारी करने का वर्ष, वैधता अवधि इत्यादि का पूर्ण विवरण दर्ज होता है। नया जारी किया जाने वाला QR CODE प्लास्टिक कोडेड एवं वाटर प्रूफ भी है,



छित्तमपुर बंदी का निरीक्षण, एई द्वारा मानक के विपरीत कराया गया हे कार्य, नोटिस जारी

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। चंदौली। विगत 28 जून 2021 को जिलाधिकारी ने छित्तमपुर बंदी का निरीक्षण किया। जिस दौरान बंदी का मजबूतीकरण एवं सेक्शन रिस्टोरेशन के कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई। सामयिक जांच में पाया गया कि एई बंधी प्रखंड मनोज पटेल के द्वारा तय मानक के विपरीत कार्य कराया गया है। जांच में अनियमितता पाये जाने पर जिलाधिकारी ने तत्काल

की अभियान प्रमुख एकता शेखर ने सूरज से समृद्धि उत्तर प्रदेश अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024 तक देश के सौर ऊर्जा लक्ष्यों की पूर्ति में भरपूर सहयोग के लिए राज्य सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति के तहत कई घोषणाएं की हैं। सरकार ने वाराणसी समेत 5 शहरों को सोलर सिटी बनाने की घोषणा भी की है। सोलर सिटी का लाभ लाभार्थी तक पहुंचे और समाज में सौर ऊर्जा का उपयोग हर स्तर तक संभव हो सके, इसके लिए ये अभियान प्रदेश के 9 शहरों में चलाया जा रहा है।

अब नगर निगम वाराणसी में जारी होगा टिन की जगह QR CODE का प्लास्टिक कोडेड लाइसेंस

अप्र ब्यूरो, वाराणसी। नगर निगम वाराणसी के अनुज्ञप्ति विभाग द्वारा वाराणसी में पहली बार रिक्शा, ट्राली, ठेला, ठेली एवं विभिन्न प्रकार की नावों को प्रतिबंध जारी की जाने वाली लाइसेंस कंप्यूटराइज्ड QR CODE के माध्यम से जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। निगम प्रशासन के अनुसार यह नगर निगम वाराणसी के लिए एक बड़ी सफलता है। उल्लेखनीय है कि जारी की जा रही QR CODE लाइसेंस में लाइसेंस धारक का लाइसेंस नंबर, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जारी करने का वर्ष, वैधता अवधि इत्यादि का पूर्ण विवरण दर्ज होता है। नया जारी किया जाने वाला QR CODE प्लास्टिक कोडेड एवं वाटर प्रूफ भी है,



छित्तमपुर बंदी का निरीक्षण, एई द्वारा मानक के विपरीत कराया गया हे कार्य, नोटिस जारी

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। चंदौली। बारिश झूम कर आने लगी है और धान का बीज भी अब रोपे जाने का समय नजदीक आ गया है। ऐसे में पूरी गर्मी समाप्त हो जाने के बाद भी जनपद में किसानों के गेहूं की खरीद पर्याप्त नहीं हो पाई है। किसान जितने किंटल का अपना पंजीयन टोकन लेकर आते हैं मोके पर गेहूं लाने पर उसकी आधी खरीद की जा रही है। उक्त भ्रष्टाचार का मामला चन्दौली जनपद में लीलापुर स्थित नवीन मंडी का है। यहां कुल चार क्रय केन्द्र खोले गए हैं। जिसका एक केन्द्र प्रभारी प्रदीप पाण्डेय है, जो हर समय कार्यलय से गायब मिलता है। ऐसा सिर्फ किसानों का ही कहना नहीं है यह स्थानीय ए.डी.एम कुमार अपनी कई निरीक्षणों के बाद कह रहे हैं।

चन्दौली के डी.एम. नहीं देखते षाड्सएप संदेश, तो फिर क्यों इंस्टाल है उनके नम्बर पर षाड्सएप

अनिवार्य प्रश्न, ब्यूरो संवाद। चंदौली। स्थानीय जिला अधिकारी का षाड्सएप नंबर चलता तो है पर उस पर कोई संदेश देखा नहीं जाता। केन्द्र और राज्य सरकार जहां जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया व डिजिटल माध्यम का सहारा ले रही है वहीं जनपद का सुन्न व बेहोश प्रशासन अभी तक सुस्त और सोया हुआ ही है। वैसे तो जनपद के जिला अधिकारी का नंबर 9454417576 षाड्सएप पर सक्रिय है, उसपर उनकी डी.पी. भी लगी है और डाटा सेवा ऑन होने से संदेश की डिलीवरी भी होती है लेकिन संदेश पढ़ा नहीं जाता है। हालांकि किसानों जनता के द्वारा भेजे गए संदेशों के फिक्र है, साहब तो डीएम हैं वह किसी

क्रेता-विक्रेता स्वयं करा सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री, किन्तु अधिवक्ताओं को माध्यम बनाने को मनाही नहीं

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। वाराणसी। प्रदेश के स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं निबंधन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने अपने एक पत्र में कहा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 32 के तहत रजिस्ट्री हेतु लेखपत्रों के प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अधिवक्ताओं के आवश्यक रूप से सम्मिलित होने की कोई बाध्यता ना पहले थी न अब है। क्रेता-विक्रेता अगर चाहे तो अपना लेखपत्र रजिस्ट्री कार्यालय में स्वयं प्रस्तुत कर लेखपत्रों की रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया में अधिवक्ताओं को सम्मिलित करना या ना करना पूर्णतया क्रेता-विक्रेता के विचार पर है। उनके अनुसार 2017 में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को



ऑनलाइन किये जाने के बाद से विभागीय वेबसाइट पर लेखपत्रों के स्वसुजित किये जाने की व्यवस्था जनसामान्य के लिए उपलब्ध करायी गयी है, इसके माध्यम से क्रेता-विक्रेता रजिस्ट्री हेतु लेखपत्र स्वयं तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत पक्षकार अपने सर्किल रेट का पता लगा सकते हैं एवं स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान विभिन्न माध्यमों से भी कर सकते हैं। जान सामान्य में प्रचार प्रसार हेतु

चंदौली में गेहूं खरीद में हावी भ्रष्टाचारी, मेठ व पल्लेदार बनते हैं केंद्र प्रभारी, 30 रुपये किंटल ली जाती है पल्लेदारी

अनिवार्य प्रश्न, ब्यूरो संवाद। चंदौली। बारिश झूम कर आने लगी है और धान का बीज भी अब रोपे जाने का समय नजदीक आ गया है। ऐसे में पूरी गर्मी समाप्त हो जाने के बाद भी जनपद में किसानों के गेहूं की खरीद पर्याप्त नहीं हो पाई है। किसान जितने किंटल का अपना पंजीयन टोकन लेकर आते हैं मोके पर गेहूं लाने पर उसकी आधी खरीद की जा रही है। उक्त भ्रष्टाचार का मामला चन्दौली जनपद में लीलापुर स्थित नवीन मंडी का है। यहां कुल चार क्रय केन्द्र खोले गए हैं। जिसका एक केन्द्र प्रभारी प्रदीप पाण्डेय है, जो हर समय कार्यलय से गायब मिलता है। ऐसा सिर्फ किसानों का ही कहना नहीं है यह स्थानीय ए.डी.एम कुमार अपनी कई निरीक्षणों के बाद कह रहे हैं।



अनिवार्य प्रश्न, ब्यूरो संवाद। चंदौली। बारिश झूम कर आने लगी है और धान का बीज भी अब रोपे जाने का समय नजदीक आ गया है। ऐसे में पूरी गर्मी समाप्त हो जाने के बाद भी जनपद में किसानों के गेहूं की खरीद पर्याप्त नहीं हो पाई है। किसान जितने किंटल का अपना पंजीयन टोकन लेकर आते हैं मोके पर गेहूं लाने पर उसकी आधी खरीद की जा रही है। उक्त भ्रष्टाचार का मामला चन्दौली जनपद में लीलापुर स्थित नवीन मंडी का है। यहां कुल चार क्रय केन्द्र खोले गए हैं। जिसका एक केन्द्र प्रभारी प्रदीप पाण्डेय है, जो हर समय कार्यलय से गायब मिलता है। ऐसा सिर्फ किसानों का ही कहना नहीं है यह स्थानीय ए.डी.एम कुमार अपनी कई निरीक्षणों के बाद कह रहे हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा की गई तमाम घोषणाओं के बाद भी जनपद का हाल जैसा का तैसा है। वैसे तो सरकार घोषणा कर रही है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार अब-तक लगभग 13 प्रतिशत अधिक मात्रा में गेहूं की खरीद की गई है, लेकिन यहां सच्चाई कुछ और ही है। जिले के किसान अपने गेहूं को लेकर दर-दर भटक रहे हैं और उनकी उजकी की मानक भर भी खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों का ही नहीं स्थानीय अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि सेंटर प्रभारी ज्यूटी पर नहीं मिलता है। वह हर दम गायब रहता है। किसानों के अनुसार यहां

अनिवार्य प्रश्न यह है कि इतने वादों के बाद भी सरकारों के दावों और और राज्य सरकार के गेहूं खरीदी व्यवस्था सुदृढ़ करने के तमाम आश्वासनों के बाद भी जिले के अधिकारी गैरजिम्मेवार, सुन्न और सुस्त

क्यों है? यहां तक कि सैयदराजा-बरहनी के अनेक किसानों ने आंदोलन भी किया, उसके बाद भी इन भ्रष्टाचारियों का ध्यान मेहनत कर जीने वाले कृषकों की संवेदना के ऊपर व उनकी पीड़ा पर क्यों नहीं जा रहा? यही चंदौली जनपद की सबसे बड़ी समस्या रही है और यही चंदौली के लिए सबसे बड़ा चिंतन का विषय रहा है। जब तक यहां लापरवाह व भ्रष्ट अधिकारियों के लिए तत्काल कठोर दंडात्मक कार्यवाही की व्यवस्था नहीं की जाएगी और किसानों से भ्रष्टाचार को गंभीरता से लिया जाएगा तब तक यहां के किसानों का दुख दूर हो पाएगा।

जनपद के लगभग सभी सेंटर प्रभारी गेहूं खरीद के लिए बनाए गए सेंटरों से लापता रहते हैं। यहां मानक से कम खरीद की जाती है। खरीद केंद्रों पर कई और तरह का भ्रष्टाचार भी छाया हुआ है। सरकार द्वारा निर्धारित 6.12 रुपये की जगह 30 रुपये पल्लेदारी ली जाती है। लाचार हो गया किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। पसीने से पैदा करने वाले व देश की भूख मिटाने वाले किसानों का आत्मबल अब टूट रहा है। पर बेशर्म सरकारी अधिकारी राक्षसों का सलूक कर रहे हैं।

अनिवार्य प्रश्न, ब्यूरो संवाद। आम लोगों द्वारा भेजी गई सूचना पर जब अनिवार्य प्रश्न समाचार समूह ने भी संदेश भेजा तो संदेश डिलीवर तो हुआ मगर काफी दिनों तक पढ़ा नहीं गया। संभवतः उनके नंबर पर किसी ना ही डिलीवर संदेश देखा नहीं जाता। हो सकता है किसी विभाग का या किसी अधिकारी का देखा भी जाता हो पर आम आदमी के नंबरों से भेजे गए संदेश को पढ़ा नहीं जाता।

अनिवार्य प्रश्न यह है कि आखिर यह नंबर चलाता कौन है? अगर डीएम साहब का नियुक्त कोई पीआरओ चलाता है तो क्या उनके नंबर पर आए विभिन्न संदेशों को ऑनयड करता है या सिर्फ अपने चिर परिचितों का ही संदेश पढ़ता

अनिवार्य प्रश्न यह है कि इतने वादों के बाद भी सरकारों के दावों और और राज्य सरकार के गेहूं खरीदी व्यवस्था सुदृढ़ करने के तमाम आश्वासनों के बाद भी जिले के अधिकारी गैरजिम्मेवार, सुन्न और सुस्त

लखनऊ में बनेगा डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र



लखनऊ में 1.34 एकड़ क्षेत्र में डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि चयनित कर ली गयी

अनिवार्य प्रश्न, लखनऊ। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने 29 जून 2021 को यहां लोक भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के स्मारक के रूप में सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल सराहनीय है। आकांक्षा व्यक्त की कि प्रस्तावित शोध केन्द्र बाबा साहब की गरिमा के अनुरूप उच्च स्तरीय शोध कार्य करे और शोध जगत में अपनी विशेष पहचान बनाए। उन्होंने भरोसा जताया कि यह सांस्कृतिक केन्द्र सभी देशवासियों, विशेष कर युवा पीढ़ी को बाबा साहब के आदर्शों एवं उद्देश्यों से परिचित कराने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति श्री कोविन्द को अंगवस्त्र एवं

स्मृति चिह्न प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र पर आधारित एक फिल्म भी प्रदर्शित की गयी। कार्यक्रम के प्रारम्भ में स्वर्ण वाचन के साथ शंख वादन किया गया। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संगायन व परिपाठ भी किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहब तर्क दिया करते थे कि लोकतंत्र में सरकारों का दायित्व है कि सबकी भलाई के लिए कार्य करें। वर्तमान सरकार भवतु सब मंगलम के मूलभाव को साकार कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि लखनऊ शहर से भी बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर का खास सम्बन्ध रहा है, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की 'स्नेह भूमि' भी कहा जाता है। बाबा साहब के लिए गुरु सभान, बोधानन्द जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानन्द जी, दोनों का निवास लखनऊ में ही

था। दिसम्बर, 2017 में अपनी लखनऊ यात्रा के दौरान उन्होंने (राष्ट्रपति) भदंत प्रज्ञानन्द जी की पुण्यस्थली पर जाकर, उनकी स्मृतियों को सादर नमन किया था। बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े सभी स्थल भारतवासियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। ज्ञातव्य है कि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण एक प्रेरणा स्थल के रूप में कराया जा रहा है। प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित किए जा रहे इस स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र में बाबा साहब के दर्शन एवं विचारों, उनके आदर्शों एवं शिक्षाओं तथा भारत के नवनिर्माण में उनके योगदान पर शोध करने के लिए एक सन्दर्भ पुस्तकालय एवं संग्रहालय भी स्थापित किया जा रहा है। ऐशबाग, लखनऊ में 1.34 एकड़ क्षेत्र में भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि चयनित कर ली गयी है। सांस्कृतिक केन्द्र में प्रवेश द्वार के ठीक सामने डॉ0 भीमराव आंबेडकर की 25 फीट ऊँची प्रतिमा की स्थापना के साथ ही उनकी अस्थियों का कलश भी दर्शनार्थ स्थापित किया जायेगा। सांस्कृतिक केन्द्र में पुस्तकालय, शोध केन्द्र, अत्याधुनिक प्रेक्षागृह, आभासी संग्रहालय, डॉरमेट्री, कैफेटेरिया, भूमिगत पार्किंग एवं अन्य जनसुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

योगी जी का आश्वासन? वो भूले या उनके कारखाने?

विगत 03 वर्षों में भी योगी जी का आश्वासन पूरा नहीं कर सके उनके अधिकारी, आखिर क्यों?

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। कानपुर। परिवार व बाल कल्याण के क्षेत्र में विगत 38 वर्षों से सक्रीय रूप से कार्य कर रही संस्था सुभाष चिल्ड्रेन होम के बच्चे एवं संस्था कार्यकर्ता मा0 मुख्यमंत्री के एनेक्सी भवन पंचम तल पर कार्यालय में उनके एक विशेष आमंत्रण पर उनसे दिनांक 06 जून 2018 को मिले थे। जिसमें संस्था द्वारा सुभाष चिल्ड्रेन होम के बच्चों के लिए होम को अनुदान दिलाने के लिए आग्रह किया गया था, जिस पर योगी जी द्वारा अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों के हित के लिए सुभाष चिल्ड्रेन होम को चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के अंतर्गत अनुदानित करने के लिए अनुदान सूची में शामिल करने के लिए आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन विभागीय अद्वयों के



कारण अभी तक इसमें कोई आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिस कारण अनाथ, बेसहारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुदान नहीं मिल पा रहा है। अब अनिवार्य प्रश्न यह है कि अपने दिए गये आश्वासन को माननीय मुख्यमंत्री भूल गये या उनके कारखाने? क्योंकि मुख्यमंत्री तो झूठा आश्वासन दे नहीं सकते। हां, मगर जनसुनवाईयों में उनके कारखानों की गलत जवाबी से आमजन नाराज जरूर हो रहे हैं जिससे आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी और सरकार को उनके कारखानों की करतूतों को भोगना पड़ सकता है। ज्ञातव्य हो कि बाल कल्याण समिति कानपुर नगर द्वारा लगातार बच्चों के पुर्नवासन व आश्रय हेतु उन्हें

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राशन कार्ड जारी करने के लिये विशेष अभियान चलायें राज्य : केन्द्र

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। नई दिल्ली। केंद्र ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दिया है कि आबादी के अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्ड जारी करने के लिये विशेष अभियान चलायें। केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि कोविड महामारी के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह जरूरी हो गया है कि अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान की जाये और उन्हें इस अधिनियम के दायरे में लाया जाये। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो जून, 2021 को यह परामर्श जारी किया है कि वे एक विशेष अभियान शुरू करें, ताकि शहरी व ग्रामीण इलाकों की आबादी के अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर



वर्ग की पहचान हो तथा उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) राशन कार्ड दिये जायें। इस विशेष अभियान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी एनएफएसए सीमा के तहत बची गुंजाइश को पूरा करेंगे। विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे समाज के जोखिम वाले और अत्यंत कमजोर वर्ग तक पहुंचने के उपाय करें। इस वर्ग में बेघर लोग, कचरा बिनने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चलाने वाले और अन्य लोग शामिल हैं। एनएफएसए के तहत पात्र व्यक्तियों, घरों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।

पौधा लगाने पर ही अब मिलेगी बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन : शिव राज

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। भोपाल। अब बिल्डिंग परमिशन इसी शर्त पर दी जाएगी कि मकान बनाने वाला व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाएगा। नगर निगम हो, नगर पालिका या नगर पंचायत अर्थात जिस भी स्तर का नगरीय निकाय हो बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधा लगाने की शर्त अनिवार्य होगी। घर पर जगह न होने की स्थिति में पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना और उसकी सुरक्षा करना

आवश्यक होगा। उक्त बातें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेशव्यापी अंकुर वृक्षारोपण अभियान को शुभारंभ करते समय प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा।

निवास से वर्चुअली आरंभ इस कार्यक्रम में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल उपस्थित थे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप



सिंह डंग ने कार्यक्रम में वर्चुअली मंदसौर से सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 5 जिलों के अंकुर अभियान के जिला नोडल अधिकारियों से वी. सी. द्वारा संवाद किया। कार्यक्रम में हरदा में

वृक्षारोपण गतिविधियों का फिल्म द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने अंकुर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँवों में भी ग्राम पंचायतों की यह जिम्मेदारी होगी कि जो भी मकान बने, उसमें एक पेड़ अवश्य लगे। यह शर्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले आवासों पर भी लागू रहेगी। घरों के अलावा स्कूल, पंचायत भवन, खेत

आदि में पेड़ लगाए जाएंगे। सरकारी भवनों और कार्यालयों के लिए भी यह शर्त रहेगी। मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में जितने प्लैट बनेंगे, उतने पेड़ बिल्डर को लगाने होंगे। सभी शासकीय, गैर-शासकीय भवनों के निर्माण में पेड़ लगाने की शर्त जोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि व्यक्ति स्व-प्रेरणा से भी पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पर्यावरण सुधार हमारे लिए नारा नहीं मंत्र है।

कुशीनगर तक विश्व सनातन सेना का किया गया विस्तार

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। कुशीनगर। भुजौली बाजार स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पर विश्व सनातन सेना संगठन युवा विंग कुशीनगर की बैठक 4 जुलाई 2021 को आयोजित हुई। जिसमें संगठन के संस्थापक काशी के अनिल सिंह बाहुबली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में संगठन के विस्तार के विषय और जिला में संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। प्रदेश महासचिव विशिष्ट अतिथि रितेश दूबे, जिला अध्यक्ष संदीप आनंद श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष रीतिक शुक्ला, नेबुआ



नौरंगिया ब्लॉक अध्यक्ष उदयभान गुप्ता, ब्लाक महासचिव आयुष शुक्ला, खड्डा महासचिव अतुल पांडे, धर्मेश्वर जयसवाल, दीपक जयसवाल व विश्राम गुण आदि लोग मौजूद रहे।

भुजौली बाजार के इस आयोजन में सनातन वादी संगठन के संस्थापक अनिल सिंह बाहुबली के हाथों संगठन में 20 लोगों की सदस्यता दी गई।

अनिवार्य प्रश्न, मऊ-वाराणसी। पुलिस द्वारा 19 जून 2021 को माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस-191 के सहयोगी वसूली गिरोह डी-34 के सदस्य सुरेश सिंह व डी-60 के सदस्य दिव्यांशु राय पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए कुल 01 करोड़ 83 लाख 21 हजार 850 रुपये मूल्य की अपराध से अर्जित अवैध धन से क्रय की गयी चल व अचल सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया है। यह कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा 18 जून 2021 को पारित एक आदेश के बाद किया गया। स्थानीय पुलिस के अनुसार माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी व मऊ में चिन्हित वसूली माफिया सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली जनपद

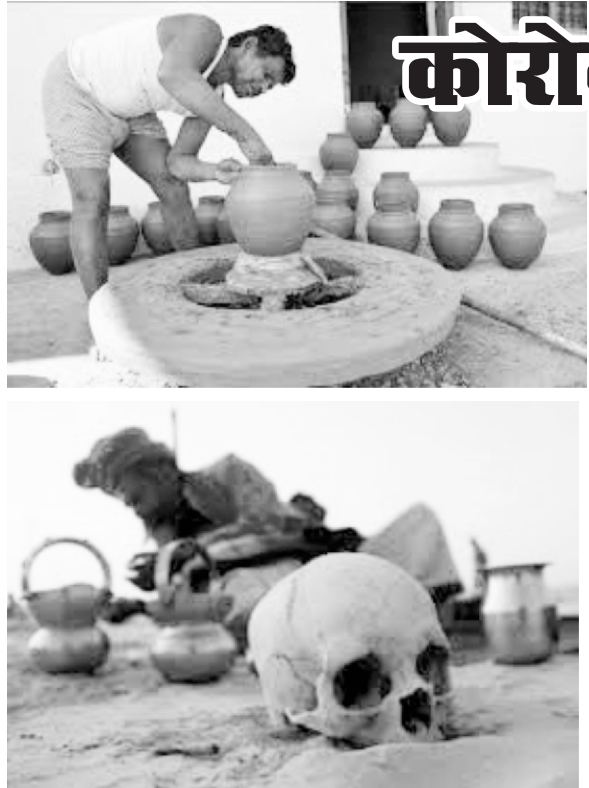
मऊ द्वारा अपनी पत्नी रुषा सिंह व अपनी भाभी प्रेमलता सिंह के नाम से क्रय किया हुआ मुहल्ला भीटी तहसील सदर स्थित आ0न0 990 रकबा 16 कड़ी जमीन व उसपे बना दो मंजिला मकान जिसमें दुकाने भी हैं जिसकी कुल बाजार कीमत 01 करोड़ 82 लाख 73 हजार 600 रूपया (जमीन तथा मकान सहित) को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्त किया गया है। साथ ही साथ उक्त मकान में यूनियन बैंक आफ इंडिया की एक शाखा व एटीएम तथा यूपी कोओपरेटिव फेडरेशन का कार्यालय है जिसका मासिक किराया 18 हजार 256 रुपये आता है जिसको आगे शासकीय कोष में जमा किये जाने का आदेश दे दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व उक्त सुरेश सिंह



की 04 करोड़ 79 लाख 95 हजार रुपये मूल्य के ईट भट्टे सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों को जब्त किया जा चुका है। इस तरह सुरेश की अब तक कुल 06 करोड़ 62 लाख 68 हजार 600 रुपये की चल व अचल सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्तार गिरोह के सहयोगी हत्यारा गिरोह

डी-60 का सदस्य तथा 06 मई 2020 को थाना कोपागंज क्षेत्र के ग्राम सहरोज में ग्राम प्रधान व उनके देवर पर जानलेवा हमला करने में शामिल दिव्यांशु राय पुत्र अरविंद राय निवासी काछीकला थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से क्रय की गयी 48 हजार 250

रुपये मूल्य की सम्पत्ति मोटरसाइकिल सूपर स्प्लेण्डर (यूपी 54 ईई 2464) को भी गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्त किया गया है। इस तरह मुख्तार गिरोह के विरुद्ध मऊ पुलिस द्वारा 19 जून 2021 को कार्यवाही करते हुए 01 करोड़ 83 लाख 21 हजार 850 रुपये मूल्य की सम्पत्ति जब्त की गयी।



कोरोना से बचने के लिए घड़ों में किए जा रहे टोने टोटके कुम्हारों के यहां घड़ा स्वत्म, हुआ मंहगा



अनिवार्य प्रश्न, कार्यालय संवाद। कोरोना से बचने के लिए उत्तर प्रदेश में टोने टोटके का दौर शुरू हो गया है। हालांकि उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में भी किसी आपदा से निपटने के लिए व सपने को पाने के लिए आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा टोने-टोटके पर भरोसा करता है। उत्तर भारत के कई जिलों में कुम्हारों के पास घड़े नहीं

रह गए हैं। वह घड़ा बना रहे हैं और वह तुरंत बिक जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इसका कारण ग्रामांचल में लोगों द्वारा कोरोनावायरस से बचाव के लिए भारी मात्रा में टोना टोटका करना एवं कर्मकांड के माध्यम से अपना बचाव करना है। उत्तर भारत में घड़े में तेल, दशांग व दूध भरकर घर से बाहर छोड़ने व और तरह कर्मकांडों के कर के आपदा से बचाव के

कई टोने टोटके चलन में हैं। जिसके कारण बाजार से इस गर्मी में मटके गायब हैं। कुम्हारों का कहना है कि वह गर्मियों में मटका अधिक बनाते थे लेकिन इसबार मांग और बढ़ गई है। लोग घड़ों का प्रयोग अपने टोने-टोटके के लिए भी कर रहे हैं। अबतक फ्रीज न खरीद पाने वाले गरीबों के पीने के पानी के लिए घड़ों का उपयोग अधिक था। लेकिन इस बार टोना

टोटका करने वाले घड़ा बनते ही उठा ले जा रहे हैं। आलम यह है कि बड़े आकार के पूरे भी घड़े के ना रहने पर खरीद लिए जा रहे हैं। चंदौली, बनारस, जौनपुर व भदोही जैसे कई जिलों में कुम्हारों ने बताया की घड़े की मांग इतनी बढ़ गई है कि मांग के अनुसार उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। वैसे भी गर्मियों में घड़ों की मांग बढ़ जाती है। क्योंकि मध्यमवर्ग परिवारों में घड़ों में भर कर पानी

टंडा करके पीने का चलन है। ऐसे में एक तो गर्मी के लिए घड़ों की मांग बढ़ जाती है दूसरे टोना टोटका भूत प्रेत के लिए भी घड़ों की खरीद बढ़ गई है। बाजार में घड़े नदारद हैं। आम आदमी में विश्वास की शक्ति बहुत प्रबल होती है। जिसके आश्रय वह तमाम आपदाओं को जी कर उससे आगे निकल जाता है। टोना टोटका ईश्वर पर आंशिक भरोसे के परिणाम स्वरूप

जिंदा है और अनेक लोग अपनी समस्याओं का समाधान टोने टोटकों के माध्यम से करते हैं। यहां तक कि कई लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए भी टोने टोटके के सहारे करते हैं। हालांकि अभी तो कुछ दिनों तक टोने टोटकों की वजह से कई लोगों को टंडा पानी नहीं मिल पाएगा। बाजार से घड़े तेजी से बिक रहे हैं इसलिए कम पड़ गए हैं और महंगे भी हो गए।

दो आईपीएस अफसरों को सीबीआई भेजेगी नोटिस



जांच सीबीआई से कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर

फाइल फोटो

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। मुम्बई। उत्तर प्रदेश के दो आईपीएस अफसरों को बयान दर्ज कराने के लिये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जल्द ही नोटिस भेजेगी। इससे पहले सीबीआई की एक टीम बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हुई हत्या के मामले में इन अफसरों से पूछताछ करने गई थी लेकिन बयान नहीं हो सके थे। वहीं कहा जा रहा है कि बागपत के पूर्व जेलर ने सीबीआई को

अपने बयान में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है इसी आधार पर सीबीआई अपनी पड़ताल आगे बढ़ा रही है। विगत दिये गए बयानों में विरोधाभास को देखते हुए सीबीआई ने इस मामले में दो आईपीएस अधिकारियों के बयान लेने को जरूरी बताया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के बागपत में नौ जुलाई, 2018 को बागपत जेल में बजरंगी की हत्या की जांच कर रही

सीबीआई बीच में सुस्त हो गई थी। अब अचानक उसकी तपतीश तेज हो गई है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक जिन पूर्व जेलर ने पुलिस को जांच में जो बयान दर्ज कराये थे, सीबीआई में उससे काफी अलग बयान दिये हैं। इस विरोधाभास को देखते ही सीबीआई ने इस मामले में दो अन्य आईपीएस अधिकारियों के बयान लेने को जरूरी बताया है।

गुजरात में भूतों पर मुकदमा दर्ज

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। अहमदाबाद। जहां आमतौर पर पुलिस को भ्रष्ट व शिकायत पर टाल मटोल करने वाले बेरहम विभाग के तौर पर जाना जाता है। उसके पास लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं जिसमें की प्रकरण में अपराधियों पर कार्रवाई ही नहीं की जाती है। वहीं गुजरात से एक ऐसी अजीबो-गरीब घटना सामने आयी है जो चकित कर देने वाली है। खबर गुजरात से सामने आई है जहां पुलिस ने दो भूतों के खिलाफ एक शिकायत लिखी है।

उसका भूतों के गैंग से सामना हुआ और भूतों ने उसे मारने की धमकी दी है। खबर के अनुसार लगभग 35 साल का यह शख्स पंचमहल के जंबुघोड़ा तालुका का रहने वाला है। वह खेत से भागकर पुलिस के पास पहुंचा और उसने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। इस अजीब अनुरोध के बावजूद पुलिस ने उस व्यक्ति को संकट से बचाने के लिए दया दिखाई और उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया।

लिखित तौर पर दर्ज हुई शिकायत के अनुसार थाने में जब शख्स पहुंचा तो वह कांप भी रहा था व काफी डरा लग रहा था। पुलिस उप निरीक्षक को लिखे अपनी शिकायत में व्यक्ति ने बताया कि जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो कैसे भूतों का एक गिरोह उसके पास आया। पावागढ़ में ड्यूटी पर तैनात पीएसआई के एक जवान मयंकसिंह ठाकोर ने बताया कि वह बहुत परेशान था। यह स्पष्ट था कि वह असामान्य रूप से व्यवहार कर रहा था। वह बहुत घबराया हुआ था। उसे शांत करने के लिए उसकी शिकायत लिखित ले ली गई।

पीड़ित शख्स का चल रहा है मनोरोग उपचार
पुलिस ने पीड़ित शख्स के परिवार वालों से भी संपर्क किया तो परिवार के सदस्यों ने जानकारी दी कि उसका मनोरोग उपचार चल रहा है। वहीं उसने बीते 10 दिनों से अपनी दवा नहीं ली थी। जब पुलिस ने सोमवार से उससे बातचीत की तो उसने बताया कि वह पुलिस स्टेशन भागकर इसलिए गया, क्योंकि उसे लगता था कि वहां भूत जाने की हिम्मत नहीं करेगा।

खबर गुजरात के पंचमहल जिले की है, जहां पुलिस ने दो भूतों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है। पंचमहल जिले के जंबुघोड़ा पुलिस स्टेशन में विगत दिनों एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक, खेत में काम करने के दौरान

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर दुराग्रह का तमाचा

एक व्यक्ति ने एक क्वार्टरक्रम में मिलते समय अचानक मार दिया तमाचा

अनिवार्य प्रश्न, कार्यालय संवाद। अपने कई दृढ़ फैसलों के लिए जाने जाने वाले एवं इस्लाम के खिलाफ कई बड़े फैसले लेने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को उसी देश के एक व्यक्ति ने एक कार्यक्रम में मिलते समय अचानक तमाचा मार दिया। सूत्रों के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति देश के दक्षिणी हिस्से के एक दौरे पर थे और वहां मौजूद कुछ लोगों से मिल रहे थे तभी एक शख्स ने उनको अचानक थपड़ मार दिया।

उन लोगों के सरोकार किससे थे और थपड़ मारने का क्या कारण था अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।



उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति दक्षिण प्रांत के इलाके के एक विशेष दौरे पर गए हुए थे। वह वहां कई लोगों, होटल मालिकों व विद्यार्थियों से मुलाकात भी किए। वायरल हुए वीडियो में राष्ट्रपति अपने कुछ अधिकारियों के साथ एक जगह बैरिकेडिंग के बाहर इकट्ठा हुए कुछ लोगों से मिलना जुलना शुरू किए तभी एक थोड़े मोटे कद काठी का व्यक्ति उनसे हाथ मिलाने के पश्चात अचानक एक तमाचा उनको मार देता है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह भी कहा गया है कि वह चांटा मारने वाला शख्स चांटा मारने के बाद 'डाउन विद मकरोनिया' जैसा नारा भी दिया था।

अंतरराष्ट्रीय प्रसारण व मीडिया की रिपोर्टों में यह कहा गया है कि इस व्यक्ति की पहचान या इसके इस हरकत के कारण का पता अभी नहीं लगाया जा सका

है। बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस घटना को लोकतंत्र का अपमान बताया है।

वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने सहृदयता को बनाए रखने एवं अपने नागरिकों से पहले की ही तरह मिलने जुलने और उनकी सेवा के अपने संकल्प को दोहराया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि वह व्यक्ति चांटा मारते समय फ्रांस की सेना का युद्ध में लगाया जाने वाला एक खास तरह का नारा 'Montjoie Saint Denis' का भी उद्घोष किया था हालांकि यह नारा फ्रांस के राजतंत्र होने के समय में प्रयोग किया जाता था।

पाकिस्तानी आतंकी के घर के पास आतंकी बम विस्फोट



जैसे के साथ तैसा

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। पापी को भी पाप जीना पड़ता है, पाकिस्तान के संबंध में यह बात सत्य सिद्ध हो गई है। लाहौर के जौहर टाउन स्थित पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के घर के पास उसकी गली में ही एक बड़ा बम विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 3 लोगों की मृत्यु एवं लगभग 18 लोगों के जख्मी होने की लाहौर

प्रशासन द्वारा पुष्टी की गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि ब्लास्ट बड़ा है और अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह आत्मघाती है। सूत्रों के अनुसार 5 घायलों की हालत काफी गम्भीर है।

उल्लेखनीय है कि एक मामले में हाफिज शहीद के घर को ही जेल बना दिया गया है और वह अपने घर से

न्यायालय में सुनवाई के लिए आया जाया करता था। उसके घर के पास उसकी गली में ही एक बड़ा बम विस्फोट हुआ है। कहा जा रहा है कि वहीं पर गली में एक कार व एक मोटर-साइकिल थी जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। लाहौर के आयुक्त उस्मान यूनिस के अनुसार अभी हादसे की वजह तथा करने वाले को लेकर कुछ साफ नहीं कहा जा सकता।

इस निर्मम वारदात में मासूम बच्चे व महिलाएं भी हताहत हुई हैं। भारत सरकार ने इस घटना पर मृतकों के लिए संवेदना प्रकट की है। और साथ ही भारत ने पाकिस्तान को आतंक की जन्म व पोषण स्थली बनने के कारण आईना दिखाते हुए हादसे को उसके कर्मों का फल बताया है।

यूडीआईडी अब को-विन 2.0 पर पंजीकरण के लिए फोटो आईडी के रूप में स्वीकार्य-केन्द्र

अनिवार्य प्रश्न संवाद, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को को-विन 2.0 पर पंजीकरण करते समय विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड को फोटो आईडी के रूप में शामिल करने के लिए कहा है। 2 मार्च 2021 को जारी

को-विन 2.0 के लिए निर्देश नोट के अनुसार, टीकाकरण से पहले लाभार्थी के सत्यापन के लिए सात निर्धारित फोटो पहचान पत्र निर्दिष्ट किए गए थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी करता है। इस कार्ड में सभी जरूरी विशेषताएं जैसे नाम, जन्म का वर्ष, लिंग और व्यक्ति-19 फोटो है, जो कोविड-19 टीकाकरण में पहचान के लिए मानदण्डों को पूरा करती है।

इन बातों को देखते हुए दिव्यांग जनों के लिए टीकाकरण तक पहुंच को और सुविधाजनक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यूडीआईडी को कोविड-19 टीकाकरण के लिए निर्दिष्ट फोटो आईडी दस्तावेज की सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं और ये जल्द ही को-विन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।

सरकार ने काले धन के बारे में आई खबरों का किया खंडन

जमाराशियों में हुई वृद्धि को सत्यापित करने के लिए स्विस अधिकारियों से मांगी गई सूचना

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। नई दिल्ली। 18 जून 2021 को भारतीय मीडिया में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें यह कहा गया कि दो साल की गिरावट की प्रवृत्ति को पलटते हुए स्विस बैंकों में भारतीयों की धनराशि 2019 के अंत में 6,625 करोड़ रुपये (सीएचएफ 899 मिलियन) से बढ़कर 2020 के अंत में 20,700 करोड़ रुपये (सीएचएफ 2.55 बिलियन) हो गई है। खबरों में यह भी कहा गया है कि यह आंकड़ा पिछले 13 सालों में जमा होने वाली राशि में सबसे अधिक भी है। सरकार ने इन तथ्यों का

खण्डन कर भारतीय प्रेस को सूचित किया है कि मीडिया में आई खबरें इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि खबरों में शामिल किए गए आंकड़े बैंकों द्वारा स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) को बताए गए आधिकारिक आंकड़े हैं और वे स्वित्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन की मात्रा का संकेत नहीं देते हैं। इसके अलावा, इन आंकड़ों में वह पैसा शामिल नहीं है जो भारतीयों, एनआरआई या अन्य लोगों ने स्विस बैंकों में किसी तीसरे देश की संस्थाओं के नाम पर रखा हो सकता है।

हालांकि, 2019 के अंत से ग्राहकों की जमा राशि में वास्तव में गिरावट आई है। प्रत्ययी संस्थाओं के माध्यम से रखे गए धन में भी 2019 के अंत से आधे से अधिक की कमी हो गई है। सबसे बड़ी वृद्धि 'ग्राहकों की ओर से देय अन्य राशि' में हुई है। ये धन बांड, प्रतिभूतियों और विभिन्न अन्य वित्तीय साधनों के रूप में हैं। वित्तमंत्रालय ने कहा है कि यहां यह बताना उचित होगा कि भारत और स्वित्जरलैंड कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता से संबंधित बहुपक्षीय सम्मेलन (एमएएसी) के हस्ताक्षरकर्ता हैं और दोनों देशों ने बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकार समझौते (एमसीएए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों के बीच कैलेंडर वर्ष 2018 और उससे आगे की अवधि के

लिए सालाना आधार पर वित्तीय खाते की जानकारी साझा करने के लिए सूचना के स्वतः आदान - प्रदान (एईओआई) की व्यवस्था सक्रिय है। दोनों देशों के बीच प्रत्येक देश के निवासियों से संबंधित वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान 2019 के साथ-साथ 2020 में भी समझौता हुआ है। वित्तीय खातों की जानकारी के आदान-प्रदान की मौजूदा कानूनी व्यवस्था (जिसका चिह्न 'मैं' अधोषित परिस्पर्तियों के जरिए होने वाली कर चोरी पर एक महत्वपूर्ण निवारक प्रभाव है) को देखते हुए, भारतीय निवासियों की अधोषित आय से स्विस बैंकों में जमा में वृद्धि की कोई महत्वपूर्ण संभावना नहीं दिखाई देती है।

इसके अलावा, जो कारक जमाराशियों में हुई वृद्धि की प्रभावी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं उनमें व्यापारिक लेनदेन में वृद्धि के कारण स्वित्जरलैंड में स्थित, भारतीय कंपनियों द्वारा जमा राशि में वृद्धि, भारत में स्थित स्विस बैंक की शाखाओं के कारोबार के कारण जमा में वृद्धि, स्विस और भारतीय बैंकों के बीच अंतर-बैंक लेनदेन में वृद्धि, भारत में स्थित किसी स्विस कंपनी की सहायक कंपनी की पूंजी में वृद्धि और बकाया डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों से जुड़ी देनदारियों में वृद्धि प्रमुख हैं। मीडिया की खबरों के आलोक में स्विस अधिकारियों से जमाराशि में वृद्धि या कमी के संभावित कारणों के बारे में अपनी राय के साथ उपयुक्त तथ्य प्रदान करने के लिए कहा गया है।

मॉडल टेनेन्सी एक्ट मंजूर, मकान को किराये पर देना अब लेगा एक व्यापार का रूप

मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया अब बनेगी औपचारिक बाजार



अनिवार्य प्रश्न, कार्यालय संवाद। नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किरायेदारी की सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें।

इससे देशभर में किराये पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद

मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा।

मॉडल टेनेन्सी एक्ट से मकान को किराये पर देने

की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा।

मॉडल टेनेन्सी एक्ट से किराये पर चढ़ाने के लिये खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा। आशा की जाती है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके।

क्या आपके अन्दर भी घघक रही है?

सच्चाई को अच्छाई को भ्रष्टाचार को शोषण को अपराध को

सबके सामने लाने की आग?

तो निश्चिन्त होकर हमसे जुड़ें।

anivaryaprashna.in

अनिवार्य प्रश्न

अखबार व वेब नेटवर्क हर जिला व थाना में वैतनिक संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि की आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीदवार संपर्क करें।

9161099088

anivaryaprashna@gmail.com

हर कलम बिकती नहीं!



उतिश द्विवेदी 'कुंठित'

प्रधान संपादक व प्रकाशक

पत्रकारिता के धर्म पहरेदारों को नमन...

इतिहास में हमेशा से अनेक पक्षों ने बलिदान देकर इतिहास को व उसके मंदिर को रोशन रखा है। राष्ट्र रक्षा में जितना योगदान सेना के जवानों का है वह पूजनीय है। ठीक वैसे ही राष्ट्र के विचार संपदा व संस्कृति की रक्षा में जितना योगदान पत्रकारिता का है व पत्रकारिता के जवानों का है उनका योगदान भी अति पूजनीय है।

दौर अंग्रेजों का रहा हो या स्वतंत्र भारत के बाद की सरकारों का पत्रकारिता घटना की सच्चाई व अवस्था के वर्णन के लिए अपने कर्म को साधने से बाज नहीं आई। वीर पत्रकारों ने हर युग में, हर दशा में उस कालखण्ड से जुड़े घटना वर्णन को समाज के सामने प्रस्तुत किया। कई बार तत्कालीन सरकारों व सत्ताओं ने पत्रकारिता एवं उसके वीरों का अनादर किया, उसे यातना दिया, लेकिन उनके कर्म यथावत बने रहे व समाज को बताते रहे कि समाज में क्या हो रहा है। वह समाज को उसके कथनी और करनी का चित्र दिखाते रहे। वह समाज में मौजूद हालातों का चित्रण करते रहे। वह आइना सरीखा सबके सामने प्रतिबिंब बन कर खड़े रहे।

अंग्रेजों के काल

में भी बहुत यातनाएं झेलना पड़ा था पत्रकारिता को। जो आज तक झेलना पड़ रहा है स्वतंत्र भारत में भी। दौर चाहे आजाद भारत के बाद सुशासन के प्रचार का हो या इमरजेंसी के दिनों में पत्रकारों के दमन का हो, बदली सरकारों में उनके भ्रष्टाचार की व्याख्या का हो, वर्तमान सरकार के गुणगान का हो, कश्मीर प्रतिबंध के समय पत्रकारों के परिधि बंधन का हो, कोविड-19 मौतों की व्याख्या का हो या विकास के समय अपना सीना ठोक ठोक कर राष्ट्रगान का हो, सभी जानकारियां बिना पत्रकारों के बलिदान व बिना पत्रकारिता के संभव नहीं थी। हर समय चाहे जीवन के उत्सव का दौर हो या शमशान पर मातम का दुखद दौर, हर समय पत्रकार अपने धर्म निर्वाह पर भाव के उच्च स्तर से कायम रहे।

बावजूद इसके कुछ प्रशासनिक महकमे के अधिकारीजनों को यह कहते सुना जाता है कि आज पत्रकारिता से जुड़े लोग पैसे लेकर खबर बेच देते हैं। उनके लिए यहां यह कहना आवश्यक हो जा रहा है कि समूची धरती का स्तर गिरा है। युग के प्रत्येक आदर्शवादी मानदंड में गिरावट आई है। हमारे नैतिक सिद्धांतों का हर सिरा टूटा है। हर आदमी

कि अपनी आत्मा की क्षति हुई है। हर आदमी का अपना कर्म स्तर स्थलित हुआ है।

तो ऐसे में पत्रकारिता भी आदमी ही करता है। कुछ गिरावट आई होगी। लेकिन हमारे दूसरे कर्मों के क्षेत्र वाले लोगों से कम गिरावट पत्रकारिता में हुई है। यह गर्व की बात है। हमारे बलिदान का स्तर आज भी उतना ही है। हमारे कर्म के साथ जुड़े हमारे त्याग भाव का स्तर आज भी उतना ही है। हमारे भारत के पत्रकारों को उनका पत्रकारिता पर गर्व होना चाहिए, और है भी। इससे महान दूसरा धर्म नहीं है।

वर्तमान कोविड के काल खण्ड में भी दिखाई दे रहा है कि क्या दिल्ली का, क्या कश्मीर का, क्या काशी का, क्या कन्याकुमारी का और क्या कोलकाता का, हर जगह, हर वर्ग व हर पद से संवाद धर्म को निभाने वाले हमारी पत्रकारिता के पहरेदार मिट रहे हैं। शान से मिट रहे हैं। फिर भी अपने कर्म के निर्वाह में पीछे नहीं हट रहे हैं। वह दुनिया के लिए दुनिया के समक्ष समाचार और सूचना के तंत्र से जुड़े हुए हैं। उन्हें खौफ नहीं मौत का। उनकी खबरों से पूरा समाज खौफजदा है लेकिन व खबरों पर खड़े हैं। वह खबरों के संग्रह व

संचारण में लगे हुए हैं। पत्रकारिता ने बहुत क्षतियां देखी है। पत्रकारिता से कईयों का साम्राज्य गिर चुका है। हो सकता है लाखों कुमार्गियों का सर्वनाश हुआ हो। लेकिन सच्चाई हमेशा ताकत पाती रही है।

बहुत नुकसान सहकर भी हमारी पत्रकारिता आज भी सजग है, सुलभ है, समर्थ है। दूसरी ओर एक गर्व की बात है कि वह अपने नुकसान को सहकर भी मुस्कुरा रही है। हताश नहीं है। पत्रकारिता को आदर्श व समाज और विश्व की आवश्यक आवश्यकता मानकर कर्पूर में भी अंजाम देने वाले जमीनी शूर वीरों से पूछा जाए तो वह साफ तौर पर कहते हैं प्रणम्य है पत्रकारिता।

आज के इस युग में जब हर कोई अपने घर में छुप जाना चाह रहा है और छुपा हुआ है। समाज का शुभ चाहने का दावा करने वाली सरकारें पत्रकारों में ही वैकसीन जैसी चीज के लिए मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी बनाकर वर्गीकरण कर रही हैं। जबकि कोविड का कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ मौतों

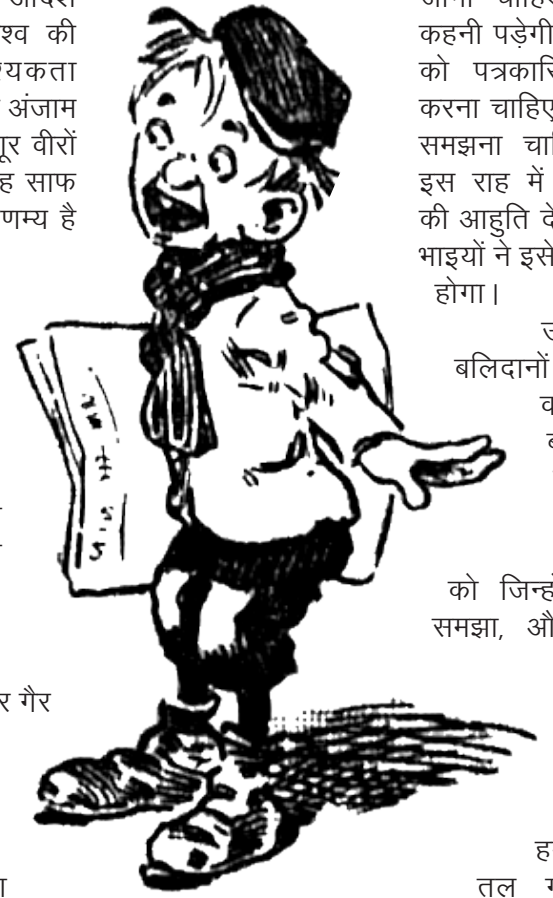
की तस्वीर सड़क पर फैली हुई है। कोई-कोई घर से बाहर अपनी जान हथेली पर लेकर निकल रहा है। सरकारें उसके लिए जुमाना तय कर रखी हैं और वसूल रही हैं। जरा सोचिए पत्रकारिता भी तो कोई चीज है जो अपने ही बच्चों को खुलेआम मौत से आंखें मिलाकर मौत की अच्छाई, बुराई, उसकी कमजोरी व उसकी ताकत लोगों में बांटने के लिए मौत के आसपास तक भेज रही है। जीवन की व्याख्या करना

सरल है पर मौत का चेहरा शब्दों से बनाना कठिन है। दौर ऐसा है जब हर कोई ठिठक गया है, लेकिन पत्रकारिता चल रही है। अपने अटूट आत्मतबल के साथ व महान धर्म के मार्ग पर।

सवाल अब भी किए जाने चाहिए। बलिदान अब भी किए जाने चाहिए। पर, अब मूल्यांकन के साथ। बलिदानों के स्तर का, बलिदानों की ऊंचाई का, समाजहित में समर्पण की गहराई का मूल्यांकन जरूर किया जाना चाहिए। एक बात कहनी पड़ेगी कि हम सभी को पत्रकारिता पर गर्व करना चाहिए। उसे प्रणम्य समझना चाहिए। सोचिए इस राह में अपने जीवन की आहुति देने वाले हमारे भाइयों ने इसे कितना चाहा होगा।

उनके आत्म बलिदानों ने इसे पावन व महान धर्म बनाकर रख दिया है। उन पत्रकारिता के शूर वीरों को जिन्होंने इसे धर्म समझा, और सब कुछ निछावर कर दिया उन्हें नमन करना चाहिए। हम अन्तः की तल गहराइयों से उन्हें नमन करते हैं।

लेखक की पुस्तक 'प्रणम्य है पत्रकारिता' से साभार उद्धृत कुछ अंश।



पत्रकारिता को प्रणम्य मानते हुए उसकी राह में अपने जीवन की आहुति देने वालों को महानतम धर्मनिष्ठ बताते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक-उतिश द्विवेदी 'कुंठित'

पड़ताल

किराएदारों की बढ़ती तकलीफ, आवासीय भवनों में किरायेदार रखने पर देना होगा अधिक गृह कर कर लोम में पड़ा वाराणसी नगर निगम, लिया गरीबों के खिलाफ निर्णय

एक तो कोरोना की मार, ऊपर से बढ़ सकता है घर का भाड़ा, घूट सकती है काशी

क्रूर हुआ नगर निगम, बढ़ेगी किराएदारों की मुसीबत

पुरानी पर गंभीर बात

आवासीय भवनों में आबाद किरायेदारी पर सीएजी की टीम ने लगा दी है आपत्ति. बढ़ेगा गृह कर. किराएदारों की ओर बढ़ेगी मुश्किलें

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। वाराणसी। नगर आयुक्त गौरांग राठी द्वारा विगत माह वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गयी गृहकर वसूली एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की गयी। नगर निगम द्वारा प्रेस को दी गई जानकारी में ऑडिट टीम द्वारा आपत्ति की गई है कि नगर निगम सीमान्तगत बहुत से ऐसे आवासीय भवन हैं जिसमें किराएदार रह रहे हैं, ऐसे भवनों से किरायेदारी के रूप नियमानुसार गृहकर नहीं वसूला जा रहा है, जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति हो रही है। बैठक में नगर आयुक्त द्वारा इस आपत्ति को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम अधिनियम में वर्णित धाराओं के अंतर्गत तत्काल कार्यवाही करने हेतु मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त श्री राठी द्वारा निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु

समस्त डाटा शीघ्र ऑनलाइन करा दिया जाय तथा गृहकर वसूली के संबंध में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। जो अब लागू भी हो चुकी होगी। उल्लेखनीय है कि नगर निगम के ऐसा करने से मकान मालिकों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन बाहर से आकर अपनी रोजी रोटी के लिए बनारस में रह रहे किरायेदारों का जीवन दूभर होने जा रहा है। कर लोम में स्थानीय नगर निगम का यह कदम सामान्य नागरिकों के लिए व प्रवासियों के लिए बोझ बनने जा रहा है।

उक्त समीक्षा बैठक में पाया गया कि गत वित्तीय वर्ष में जितने करोड़ की वसूली की गयी वह विगत वर्ष से अधिक है। यह उपलब्धि कोविड - 19 महामारी के बावजूद की गई, जो बड़ी उपलब्धि है। नगर आयुक्त गौरांग राठी द्वारा निर्देशित किया गया कि भवन के अंदर वृक्षारोपण, वाटर रैन

हार्वेस्टिंग एवं पार्किंग की सुविधाएं होने पर 2 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है, अतः इसे प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के माध्यम से भवन स्वामियों को अवगत कराया जाय। सीएजी टीम द्वारा विगत माहों में नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 का लेखा परीक्षण किया गया। हालांकि उक्त बैठक में नगर निगम की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन मकान मालिकों पर जो किराएदार रखते हैं कितना कर लगाया जाएगा या उनके गृह कर में कितना कर भार बढ़ाया जाएगा। लेकिन यह तय हो गया है कि किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर कुछ अतिरिक्त कर लगेगा। हालांकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद बनारस में किरायेदारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

अनिवार्य प्रश्न की एक पड़ताल में कई किरायेदारों ने नगर निगम के नए कर विदू के खोजने और कर बढ़ोतरी पर उसकी भर्त्सना की है। निजाम चाहे किसी विभाग का हो उसे अपने कार्यकर्ताओं की सुख-सुविधा और तनखाह बढ़ाने के लिए कर बढ़ाने पर उसका ध्यान जरूर रहता है। नगर निगम भी ऐसा ही करने वाला है।

मकानों की ही तरह पत्थर के हैं मकान मालिक कोरोना में भी नहीं छोड़े एक माह का भी किराया

मजबूर हुए रहवासी

मैं एक प्राइवेट ऑटो गैरेज में काम करता था, मुझे जीवन के खर्चे भर ही पैसे मिलते थे। जैसे-कैसे किराया देता था। लेकिन लॉकडाउन लगते ही सभी गैरेज बंद हो गए और मैं बेरोजगार हो गया। मेरे कमरे के मालिक ने मुझे हर हाल में पैसा देने के लिए बोल दिया। एक दो महीने तो मैं पत्नी के गहने बेच कर किराया दिया फिर मैं असमर्थ हो गया। अब मैं अपने एक रिश्तेदार के यहां चंद्रा चौराहे की ओर रहता हूँ। अभिषेक सिंह, मोटर मैकेनिक, पहड़िया

मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। लॉकडाउन के बाद प्राइवेट स्कूल वाले पैसा देना बंद कर दिए और मैं नौकरी से लिखित तौर निकाला तो नहीं गया लेकिन मैं बेरोजगार हो गया। मुझे अपने बनारस भोजपूर के मकान को छोड़कर अपने घर पलाही पट्टी से आगे पड़ने वाले गांव में वापस आना पड़ा और अब मैं लॉकडाउन के समाप्त होने का इंतजार कर रहा हूँ कि कब पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त होगा और मैं पुनः नौकरी पर लौट सकूंगा। कुछ पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं नया कमरा खोजूंगा। लेकिन इतना कहूंगा कि मकान मालिक बड़े निर्मम व क्रूर होते हैं। शैलेश मिश्रा, प्रइवेट टीचर, बसहॉ

मौन है सरकार

मजबूर किरायेदार

गरीबी में हजारों ने छोड़ी काशी

क्रूर मकान मालिकों को हर हाल में चाहिए किराया. नहीं कर रहे रहम

जिनकी छूटी काशी

मेरा मकान मालिक दबाव देकर किराया लेता है, मैं कैसे भी करके आधा देने को तैयार था, लेकिन उसे पूरा चाहिए था। इसलिए मजबूरन मुझे अपना कमरा छोड़ना पड़ा अब मैं अपने गांव आ गया हूँ। जब हालात ठीक होंगे तब देखेंगे की क्या करना है। इतना तो कहूंगा कि बनारस के मकान वाले अच्छे आदमी नहीं हैं। कसाई की तरह रुपये वसूलते हैं और दूसरे तो यहां कमरा मंहेगा भी है। मनीष कुमार पटेल, विद्यार्थी, लंका

मेरा मकान मालिक कोरोना के समय में भी समय से किराया देने के लिए बार-बार दबाव बनाया, मैंने घर में खाने के लिए रखे अनाज बेचकर किराया चुकाया। मेरे एक साथी ने तो पत्नी के कनफूल बेचकर किराया दिया, लेकिन वह भी पूरा समय रह नहीं पाश और उनको भी मकान मालिक ने एक महीने में देर से किराया देने के लिए मकान से निकाल दिया। कोरोना का यह बड़ा कठिन समय है, ईश्वर करे कि फिर दोबारा ना आए और किसी तरह से यह बला टल जाए। एक किरायेदार का दर्द मकान मालिक कभी नहीं समझ सकता। कोरोना में किरायेदार बरबाद हो गए हैं। कई तो बनारस से चले भी गए। सरकार भी साथ छोड़ दी है और गद्दारी की है। अशोक कुमार, कैब ड्राइवर

कहानी

बिट्टो जिज्जी

संध्या श्रीवास्तव
सिंगरा, वाराणसी



बिट्टो जिज्जी गाँव भर की दुलारी थी। चमकता गोरा रंग, लम्बे बाल, सुन्दर मुखाडा और शानदार लम्बाई। सदा सती रहती। किसी से भी मिलती अभिवादन किये बिना न रहती। बच्चों को खूब प्यार करती। बड़ी ही सरल और सज्जन बेटी थी। वो और से चाहे जितना भी हँसती, मुस्काराती परन्तु उसके हाथ और पीठ कभी-कभी गाल पर पंजे के निशान, माथे की चोट जली उँगलिया बिना कहे ही उसकी स्थिति को बयों कर देती थी।

जब वे पाँच साल की थी तभी उसके माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसका सात वर्ष का एक बड़ा भाई था। जो माँ के मरने के कारण कुछ विक्षिप्त सा हो गया था। कहते हैं कि लड़कियों में सहनशीलता और समझदारी ज्यादा होती है। पिता जी सरकारी आफिस में कहीं क्लर्क थे। सुबह सुबह उठकर उनके साथ खाना बनाने में मदद करते-करते कब निपुण हो गई पता ही न चला। वे अपना तथा भाई का भी खयाल रखती पिता के आफिस चले जाने पर दोनों भाई बहन गाँव के स्कूल में ही पढ़ने जाते। घर आकर खाना खाते थोड़ा खेल भी ले। बिट्टो जिज्जी फिर शाम का खाना बनाती। पिता और भाई को खिलाकर स्वयं भी

खाती और फिर बरतन मॉज घोकर रख देती। सुबह की तैयारी भी कर लेती। इसी तरह जिन्दगी पटरी पर आने लगी थी। पिता जी एक दिन दूसरी पत्नी ले आये। साँवली सलोनी अच्छी स्वस्थ महिला थी। उसने आते ही देखा कि अरे! वह यहाँ तो एक नौकर और एक नौकरानी पहले से ही है उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। फिर वह कुछ भी काम नहीं करती। बिट्टो जिज्जी पर अपना पूरा अनुशासन उड़ेल देती। उसे दिन भर काम में लगाये रहती। छोटी बच्ची से यदि कुछ भी गलती हो जाती तो वह उसे दो लात मार कर ढकेल देती और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती। बिट्टो जिज्जी डर के मारे न खाना खाती न कुछ बोलती। छिप-छिप कर रोती किसी से कुछ न कहती। सौतेली माँ के भाई बहन आते तब तो उसकी और भी बुरी गति हो जाती। कोई कहता पानी ला दे। कोई कहता रामय से चाय नहीं मिला।

सभी उसे नौकरानी ही समझते थे। अब सौतेली माँ के तीन बच्चे थे। उन सबकी जिम्मेदारी बिट्टो जिज्जी की थी वे कब बच्ची से बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। एक दिन उनसे बच्चे को चम्मच से दूध पिलाते समय दूध का कटोरा छलक गया। तो

उनकी विमाता ने चुल्हे की जलती लकड़ी निकालकर उसी से उनका हाथ जला दिया। अब तुझसे कभी दूध नहीं गिरेगा। बिट्टो जिज्जी बड़ी धार्मिक थी इस सभी कार्यों के बीच वह अलसुबह ही उठकर स्नान करती और फिर सूर्य को जल चढ़ा कर ही कुछ खाती पीती। बिट्टो बच्ची तो थी ही अभी उग्र ही क्या थी? अलगानी पर कपड़े सूख रहे थे। उसे न जाने क्या सुझी वह साड़ी के बीच में अपना सिर डाल कर गोल गोल घूमने लगी। उसके सारे बाल साड़ी में गोल गोल फस गये।

उसे खोलने के लिए उतना ही उलटा चक्कर लगाना पड़ता तब उसके बाल मुक्त हो पाते। परन्तु यह क्या विमाता आ पहुँची। उन्होंने देखा कि उसकी साड़ी के साथ खिलवाड़ कर रही है तो उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने आव देखा न ताव साड़ी पकड़कर खींच दी। उसके सारे बाल जो साड़ी में फंसे थे जड़ से उखड़ गये और उस स्थान से खून रिसने लगा। बिट्टो चिल्ला उठी और जमीन पर गिर पड़ी। काफी देर बाद उसे होश आया तो उठी और घाव पर फिटकरी लगाकर चुपचाप काम में लग गई। किससे क्या कहती? बाप को तो किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। धीरे धीरे गाँव भर

में सबको उस पर हो रहे अत्याचार के विषय में पता चल गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे।

परन्तु सभी इस बात पर उलझकी की प्रशंसा करते कि धन्य है ऐसी लड़की जो किसी को कष्ट भी नहीं बताती। जब लड़की बड़ी हो व गाँव भर में सबको पता हो कि उसके सिर पर माँ का साया नहीं तब कुछ एक दिन बिट्टो खेत में कुछ सब्जी लेने चली गई। उसने सोचा ताजा पालक खेत में ले आये। दोपहर का समय था। एक मनचला वहीं कहीं घूम रहा था जैसे ही उसने बिट्टो को देखा उसकी ओर 'अरे मोर रानी' कह कर दौड़ पड़ा। बिट्टो उसकी हरकतों के अनजान नहीं थी। वह दौड़ पड़ी और हॉफती हुई घर वापस बिना पालक लिए आ गई। पूछने पर उसे माँ को बताना ही पड़ा। अब तो उसकी जो टुकाई हुई कि माता उसको कहने लगी— गई थी नैन मटका करने। आज तुम्हारी आँखें ही फोड़ दूंगी। और उसने उसकी आँखों पर काफी प्रहार किया परन्तु प्रभु की कृपा से उसकी आँखें बच गईं। कहते हैं कि भगवान

अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। प्रतिदिन सूर्य की उपासना करने वाली बिट्टो पर एक दिन भुवन भास्कर प्रसन्न हो उठे। गाँव में किसी के घर शादी थी एक भाई और बहन भी आये थे। बिट्टो भी गई थी और झूम-झूम कर शादी का गाना गा रही थी उसकी ढोलक की थाप पर सभी झूम रहे थे। अचानक उन भाई बहन की भी नजर उसपर पड़ी। लड़का किसी उच्च पद पर आसीन था। उसने बिट्टो के विषय में पता किया और उसी रात को ही उसकी बहन ने बिट्टो के पिता से बात की और बिट्टो को अंगूठी पहना कर अपना बना लिया। लड़के की कोई माँग नहीं थी। बस उसने बहू के जोड़े में लड़की को बिदा कराया।

आज बिट्टो 15 साल बाद अपने कलक्टर पति और दो बच्चों के साथ गाँव वापस आई है। पूरा गाँव उससे मिलने आया है। उसके बच्चे भी सबसे मिल कर के प्रसन्न हैं।

लघुकथा



सीमा गर्ग 'मंजरी'
मेरठ, उत्तर प्रदेश

बुढ़ी माँ की बहूआ



आज महेश साइकिल पर पैडल मार रहा था किन्तु लगता था कि जैसे साइकिल पीछे की ओर बढ़ रही है। क्योंकि उसका दिमाग तो अपने बेटे के जन्मदिन की फरमाईश पर उसका मनपसंद तोहफा खरीदने की योजना में लगा था।

शहर में कोरोना महामारी से भयानक संक्रमण फैला था। अस्पताल में अटेंडेंट महेश का काम भी काफी बढ़ गया था। महेश ने कुछ काम निबटाया ही था कि एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे को रेमडीसिवर इंजेक्शन लगाने के लिए उससे माथापच्ची करने लगी। अन्दर स्टोर में अन्तिम बचा एक रेमडीसिवर इंजेक्शन रखा भी था।

किंतु उसी समय महेश को अपने बेटे का चेहरा और उसके तोहफे की याद आ गई। जिसके कारण उसके दिमाग में एक खुराफात सिर उठाने लगी। और उसने वह इंजेक्शन तुरंत छिपा लिया और उस बूढ़ी औरत से कहा कि—

'इंजेक्शन का स्टॉक समाप्त हो गया है।'
महेश की बात सुनते ही वो औरत रो-रोकर अपने बेटे के जान की भीख मांगने लगी।

वो बहुत रोई और महेश के पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगी। 'किसी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो बेटा!'

'मैं तुम्हारा अहसान जिंदगी भर मानूँगी!'

'बेटा भगवान तुम्हारे बच्चों को खुशहाल रखें!'

'माँ जी, आप समझती क्यों नहीं हैं?'

इस टीके की अस्पताल में अभी व्यवस्था नहीं है।

'स्टॉक समाप्त हो गया है।'

महेश ने बूढ़ी माँ के जिद्द करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की।

'अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ?'

'आप बाहर जाकर टीका खरीदकर ले आओ। हम आपके बेटे को रेमिडीसिवर टीका लगा देंगे।'

'तीन सौ रुपए उस इंजेक्शन की कीमत थी बूढ़ी माँ ने अपने पल्लू में से बँधे पाँच सौ रुपए का मुड़ा तुड़ा आखिरी बचा नोट महेश के सामने रख दिया। लेकिन पता नहीं महेश उस समय किस मिट्टी का बन गया था कि उसका दिल नहीं पसीजा।

महेश ने बाहर से खरीदकर लाने का पर्चा बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दिया और दूसरे कामों में व्यस्त हो गया।

कुछ समय बाद

अस्पताल से बाहर निकल कर उसने वही इंजेक्शन किसी और जरूरत मंद से सौदा करके तीस हजार रुपए में बेच दिया।

शाम होते ही तीस हजार रुपए महेश की जेब में गर्माहट भर रहे थे। रास्ते में पड़ने वाली स्मार्ट फोन की दुकान से उसने बेटे का मनपसंद तोहफा 'रैडमी-8 प्रो' मोबाइल सुन्दर गिफ्ट पैक कराया और जल्दी-जल्दी पैडल मार कर घर की ओर बढ़ चला।

घर के बाहर ही अनेक लोगों की भीड़ देख कर उसने साइकिल एक ओर रखी कर दी और आगे बढ़कर माजरा समझने की कोशिश करने लगा। महेश को आता हुआ देखकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। महेश भौंचक्का सा जल्दी से घर में घुसा तो सामने ही ऑगन में खून से लथपथ उसके बेटे की लाश पड़ी थी। बेटे को बाजार से सामान लाते हुए घर के नजदीक ही कोई लॉरी वाला टक्कर से रौंदकर भाग गया था।

महेश दहाड़े मारकर बेटे की लाश के ऊपर गिर पड़ा।

उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। महेश की नजरों के सामने वो रोती हुई बूढ़ी औरत और उसके जवान बेटे के चेहरे गड्ढमड्ढ होने लगे।

गुजुल



डॉ० रजनी अग्रवाल
'वाग्देवी रत्ना'
लेखिका वाराणसी की
वरिष्ठ साहित्यकार हैं।

मर गई इंसानियत

जिंदगी की हर कहानी क्यों रुलाती है हमें? मर गई इंसानियत किससे सुनाती है हमें! मुफलिसी की मार जब पड़ती हमारे पेट पर, रोटियों के दो निवालों को सताती है हमें!

आदमी ही आदमी को चूसता है हर जगह, भान कुर्सी का यहाँ सत्ता दिलाती है हमें! जिसम की होली जलाकर लोग खुशियाँ बँटते, बेबसी इन हादसों में आजमाती है हमें!

आज उपवन में खिली क्यारी यहाँ मुरझा गई, घूप महलों की नसीबी ये जताती है हमें!

हर तरफ 'रजनी' यहाँ जुल-मों सितम छाए हुए, पल रही नफरत दिलों में वो जलाती है हमें!

कोरोना महामारी के रोकथाम में भारतीय चिकित्सा पद्धति 'आयुर्वेद' का काफी सफल

वैद्य रोहित पाण्डेय

मर्म चिकित्सक व योग प्रशिक्षक।

महामारी अर्थात् जनमार या जनपदोर्ध्वंश समय-समय पर मानव सभ्यता की क्षति करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस का संक्रमण विकराल रूप लेकर महामारी ही बन चुका है। मूलतः यह व्याधि प्राणवह स्रोतस (श्वसन प्रणाली) का रोग है। इसमें रोगी को जुकाम, खासी, बुखार व सांस की समस्या होने के अनेक लक्षण मिलते हैं।

इस रोग का प्रसार संक्रमित रोगी की श्वास, उसके द्वारा प्रयोग में लायी गई वस्तुओं को छूने के पश्चात हाथ, मुख या नाक पर लगाने से होता है। यह किसी भी व्यक्ति को हो सकता है।

किंतु यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दृढ़ है तो आप पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है तथा दवा व अन्य उपायों से रोगी के शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को पुनः मजबूत करने से यह रोग स्वतः शांत हो जाता है।

सभी सार्वजनिक स्थानों को नियमित अंतराल पर सेनेटाइज किया जा रहा है, जन सामान्य को मास्क व सेनेटाइजर के प्रयोग करने व भीड़ भाड़ से बचने का सुझाव दिया जा रहा है। पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति द्वारा त्वरित, आंशिक व लाक्षणिक लाभ भी दिया जा रहा है।

किंतु यह सभी उपाय कोरोना संक्रमण का रोकथाम कर पाने में पूर्ण सहायक सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण है अधर्म। आचार्य चरक द्वारा जनपदोर्ध्वंश अध्याय में कहा गया है कि मानव द्वारा उसके सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों को न करना ही अधर्म है। इस कारण से देश-काल-वायु-जल दूषित होकर महामारी को उत्पन्न करते हैं।

ऐसी आपदा में आयुर्वेद महामारी के रोकथाम में काफी मदद कर सकता है। इतिहास में इसके पर्याप्त प्रमाण भी मौजूद हैं जब हमारे समुदायों को निरोग करने व भयानक संक्रामक रोगों से बचाने में प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान ने महती भूमिका निभाई है।

ऐसे समय में आयुर्वेद के अनुसृत निम्न उपाय अपनाए जा न चाहिए—
निदान परिवर्जन—
राग उत्पादक कारणों से दूरी बनाएं।
धूपन—
धूप, नीम, लोध, अगरु, गुग्गुलु, लोबान का उपयोग करें।
एकांतवास—
प्रभावित स्थान व व्यक्ति से उचित दूरी रखें।
औषधि भोग—
स्वस्थ व्यक्ति द्वारा रसायन का प्रयोग जैसे च्यवनप्राश खाएं।
व्याधि अनुरुप चिकित्सा—
चूँकि यह प्राणवाह स्रोतस की व्याधि है, अतः इस हेतु कवल, गंडूष, शिरोविरेचन व प्राणायाम अधिक लाभप्रद है।

कुछ प्राथमिक व घरेलु उपाय भी बेहद कारगर हैं उनका भी प्रयोग करके लाभ लिया जा सकता है। ये निम्न हैं—
काढ़ा, तुलसी, सोंठ, मरीच, पिप्पली, कवल— गर्म जल, हल्दी, नस्य— अणुतेल, सरसों तेल, भाप, औषधीय प्रयोग— बच्चों में— नियमित स्वर्ण प्राशन, वयस्क में— गुड्डी घन वटी 500 मिलीग्राम त्रिभुवन कीर्ति रस 500 मिलीग्राम महासुदर्शन घन वटी 500 मिलीग्राम शिरिषादि क्वाथ 20 मिलीग्राम व्योषादी / एलादी / खादिवादी गुटिका — चूषण



IPRESS
स्याही प्रकाशन
यहाँ सब कुछ छपता है।
अब आपकी सेवा में अपनी अनेक शाखाओं के साथ
शाखाएँ :
● भोजपुरी ● शिवपुर ● सिस्सा ● थानागढ़ी ● शहाबाबाद, चन्दौली
ई-बुक, किताब, अखबार, पत्रिका, पल्लेवस, ग्लोशाइन बोर्ड, पोस्टर, पैम्पलेट, आई-कार्ड, विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, डायरी, कैलेंडर, स्टीद, टी-शर्ट, कप इत्यादि की रचना और छपाई होती है।
मुख्यालय : नारायणपुर, भोजपुरी-सिन्धोरा रोड, वाराणसी, 9161099088
syahiprakashan@gmail.com

हेतु आणि व उर्वी मर्म उत्प्रेरण उपरोक्त व अन्य औषधियों का प्रयोग वैद्यकीय परामर्श के पश्चात करें।
घरेलू उपचारों के अतिरिक्त औषधि के इस्तेमाल करने से पहले चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है।

अग्रहार मंथन

फार्म IV
1- प्रकाशन का स्थान पता:- चोड़सारी, अमिलिया, शहाबाबाद, चकिया, चन्दौली, उ० प्र०, 232118
2- प्रकाशन की निपट अवधि:- मासिक
3- मुद्रक का नाम:- छतिस कुमार द्विवेदी
: राष्ट्रीयता:- भारतीय
: पता:- चोड़ सारी, अमिलिया, शहाबाबाद, चकिया, चन्दौली, उ० प्र०, 232118
4- प्रकाशक का नाम:- छतिस कुमार द्विवेदी
: राष्ट्रीयता:- भारतीय
: पता:- चोड़ सारी, अमिलिया, शहाबाबाद, चकिया, चन्दौली, उ० प्र०, 232118
5- संपादक का नाम:- छतिस कुमार द्विवेदी
: राष्ट्रीयता:- भारतीय
: पता:- चोड़ सारी, अमिलिया, शहाबाबाद, चकिया, चन्दौली, उ० प्र०, 232118
6- उन व्यक्तियों के जो सम्पादन पत्र के स्वामी हैं और उन भागीदार व शेयरधारकों के जो कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के धारक हैं नाम व पते-
छतिस कुमार द्विवेदी, चोड़सारी, अमिलिया, शहाबाबाद, चकिया, चन्दौली, उ० प्र०, 232118
मैं छतिस कुमार द्विवेदी घोषणा करता हूँ कि उक्त दो गई विनिर्दिष्टी मेरे सत्य ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही हैं।
तारीख
प्रकाशक के हस्ताक्षर
छतिस कुमार द्विवेदी

2,000 करोड़ की कोकीन जब्त

निषिद्ध पदार्थ का वजन 302 किलोग्राम था



लिया, जिसमें लकड़ी के लड़े लाए जाने की घोषणा की गई थी। संदिग्ध कंटेनर मूल रूप से पनामा से चला था, जो एटवेर्प और कोलम्बो बंदरगाहों के रास्ते लाया गया।

जांच में संदिग्ध कंटेनर में लकड़ी के लड़ों की कतारों के बीच 9 बैग पाए गए। इन बैगों को खोलने पर उनमें पैकिंग सामग्री की कई परतों में लिपटी 302 सफेद कम्प्रेस्ड रंग की ईंटें

मिलीं। इस निषिद्ध पदार्थ का वजन 302 किलोग्राम था और इसके संदिग्ध रूप से कोकीन होने की आशंका है।

इस निषिद्ध पदार्थ के साथ लकड़ी के लड़ों को भी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। इस खेप के मूल स्थान और छिपाकर लाए गए मादक पदार्थों के बारे में आगे की जांच की जा रही है।

लाखों मर गए, कब तय होगी जिम्मेदारी

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। नई दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्रियाकलाप को संदिग्ध बताते हुए अमेरिका से दिया जाने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुदान रोक दिया था। उन्होंने दावा पूर्वक कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की लापरवाही व संदिग्ध कार्यों की वजह से ही अमेरिका में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। अमेरिका के लाखों लोग मारे गए और भारत में भी मर रहे हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन समय रहते सतर्क रहने की घोषणा एवं और नोटिफिकेशन जारी किया होता तो विश्व में इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक जांच में 10 सदस्य टीम बुहान कोरोनावायरस की जांच करने के लिए गई थी। आई जानकारियों में चीन के स्थानीय वैज्ञानिकों ने भी जांच में सहयोग किया। जिसमें पाया गया

कि यह वायरस वहां से नहीं निकला है। लेकिन विश्व के अनेक देश आज भी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक चीन के स्थानीय वैज्ञानिकों के साथ निष्पक्ष जांच कर पाए होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस जांच पर आज तक सवाल उठ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह जांच मार्च और अप्रैल महीने के आसपास की गई थी। तब से विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार अपनी घोषणाओं में यह कहता आया है कि कोविड 19 वुहान से नहीं आया है जबकि विश्व के अनेक देश व नागरिक यह मान रहे हैं कि चीन की खामियों व विनाशकारी योजनाओं के कारण कोरोनावायरस का जन्म हुआ और हमारे विश्व के अनेक बेगुनाह लोग मर गए। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी सही जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसा क्यों है? कोरोनावायरस के प्रकोप में आकर जनमानस सहम गया है। एक दूसरे



को, एक दूसरे के रिश्तेदारों को मरते हुए देख कर पूरे उत्तर भारत में और महाराष्ट्र में जैसे आदमी टूट कर बिखर गया। अन्तर्दिष्ट को करते समय दाह संस्कार के स्थलों पर और घाटों पर अधिकतर व औने पौने दाम पर लकड़ियां व जलाने की सामग्रियां बिकने लगीं। अस्पताल ही नहीं श्मशान में भी बाजार ने अपने पूरे स्वभाव को धारण कर लिया। जहां कोई संवेदना नहीं थी सिर्फ खरीद और बिक्री थी। गरीबों में ऐसे बहुत लोग जो इलाज में ही बहुत पैसा

खर्च करके कर्ज कर लिए होते थे वह जलाने के समय श्मशान में जाकर परवाह करने लगे। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि कुछ अपराध और हत्याओं के शव भी इस दौर में नदी में ही विसर्जित करवा दिये गए। हालांकि ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी अन्यथा शिकायत पुलिस तक आती और दर्ज होती तो आंकड़ों में आ जाती।

साथ ही साधारण मौतों के लोग भी कोरोना होने के भय से व घाटों पर लगी लंबी कतार से परवाह करने में रुचि लेने लगे।

जिसके कारण लाशों का ऐसे मिलना हो रहा था जैसे नदियों में प्लास्टिक तैर रहा हो। गाजीपुर, बक्सर, बलिया यहां तक कि काशी में भी लावारिस लाशें नदी किनारे पाई गई हैं। जो काफी चिंताजनक है। लाशों के परवाह करने के अनेक कारण बताए गए हैं। लेकिन सभी कारण सामाजिक व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था व समूचे प्रशासनिक तंत्र पर प्रश्न खड़े करते हैं?

हमारे अगले अंक में पढ़ें इस विषय पर विशेष कवरेज व स्पेशल स्टोरी।

मुम्बई में जल्दी ही शुरू होगी वॉटर टैक्सी और रोपैक्स सेवा

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। नई दिल्ली। मुम्बई की भीड़ भरी सड़कों से परिवहन का भार कम करने और पर्यावरण अनुकूल जल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोपैक्स फेरी सेवा के 4 नए मार्गों और वॉटर टैक्सी सेवा के 12 नए मार्गों को दिसम्बर, 2021 तक परिचालन योग्य बनाने की योजना बनाई गई है।

इस समय रोपैक्स (रोल ऑनरोल ऑफ यात्री) सेवा भाऊचा घक्का से मांडवा (अलीबाग) तक परिचालित की जाती है। इस के तहत 110 किलोमीटर की सड़क यात्रा को जल मार्ग के जरिए घटाकर 18 किलोमीटर किया गया है और इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों का यात्रा समय 3-4

घंटे से घटकर मात्र एक घंटा रह गया है। इस फेरी सेवा के लाभों को देखते हुए मुम्बई के अन्य विभिन्न मार्गों पर भी इस तरह की सेवाएं शुरू करने की योजना है।

नए मार्गों का विस्तृत नक्शा इस प्रकार है। रोपैक्स फेरी सेवा के 4 नए मार्ग और वॉटर टैक्सी सेवा के 12 मार्ग खुलने से मुम्बई के दैनिक यात्रियों को बहुत लाभ होगा। इससे यात्री प्रदूषण मुक्त, शान्तिपूर्ण और समय की बचत करने वाली यात्रा कर सकेंगे और उनका यात्रा समय और खर्च बचेगा तथा कार्बन फुटप्रिंट में भी पर्याप्त कमी आएगी। इससे बड़ी संख्या में पर्यटकों और दैनिक यात्रियों को मुम्बई शहर के



हर हिस्से की यात्रा में आसानी होगी।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया ने महाराष्ट्र के मुम्बई में शहरी जल परिवहन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए विगत महीने आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, मुम्बई बंदरगाह के अध्यक्ष और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारी तथा अन्य हितधारक मौजूद थे।

15 सितंबर, 2021 है पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) के लिए ऑनलाइन नामांकन व अनुशंसाएं अभी जारी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2021 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन व अनुशंसाएं केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल <https://padmaawards.gov.in> पर ही ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी। वर्ष 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा हर

साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के उत्कृष्ट कार्य या योगदान को सराहा जाता है। ये पुरस्कार सभी क्षेत्रों/विषयों जैसे कि कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान व इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग, इत्यादि में विशिष्ट एवं असाधारण उपलब्धियों व सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं।

जाति, पेशा, पद या महिला-पुरुष के आधार पर भेदभाव

किए बिना ही सभी व्यक्ति ये पुरस्कार पाने के पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़ सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत लोगों सहित समस्त सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।

सरकार पद्म पुरस्कारों को 'जन पद्म' के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्व-नामांकन सहित नामांकन व अनुशंसा करें। उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां



पद्म पुरस्कार 2021 (Padma Awards 2021)

वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच सराहने जाने के योग्य हैं और जो निःस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। नामांकन/अनुशंसा में वे सभी संबंधित विवरण शामिल होने चाहिए जो उपर्युक्त पद्म पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट किए गए

हैं, जिसमें एक विवरणात्मक या अनुशंसित उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) भी शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही अनुशंसित व्यक्ति की अपने संबंधित क्षेत्र व विषय में हासिल की गई विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों व सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

दी वर्ल्ड जर्नी



पर्यटन-संस्कृति का बेजोड़ संगम है मध्याप्रदेश

दी वर्ल्ड जर्नी डेस्क

नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत स्थापत्य कला के धनी मध्यप्रदेश का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति पूरे भारत में अद्वितीय है। स्थानीयों के अनुसार जिस तरह हीरे की असली परख जौहरी को ही होती है उसी तरह मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार और विकास की असीम संभावनाओं को तलाशने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी काम किया है। उन्होंने न सिर्फ प्रदेश के नैसर्गिक और लुभावने स्थलों को पर्यटन के लिए विकसित किया बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के

अवसर भी पैदा किए हैं। अब पर्यटन सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा बल्कि रोजगार, स्थानीय संस्कृति और खान-पान, कला और स्थापत्य कला का केंद्र-बिंदु भी बनके उभरा है।

कोरोना काल में भी हुए नवाचार

पर्यटन विभाग ने कोविड के बाद की परिस्थितियों के अवसरों को तलाशना जारी रखा। नित नए प्रयासों और नवाचारों से मध्यप्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को दृढ़ करने के उद्देश्य को लेकर सतत प्रयास रहा। पर्यटन के प्रमुख क्षेत्र वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, लेइश्य टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म की सभी संभावनाओं को विकसित

किया गया। सभी उम्र के व्यक्तियों की रुचियों को ध्यान में रखकर गतिविधियाँ आयोजित की गई। रूरल टूरिज्म, हेरिटेज वॉक, इंस्टाग्राम मांडू टूर, साइकिल टूर, आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार, म्यूजिकल कंसर्ट और फूड बाजार जैसे नवाचार किये गये।

एडवेंचर टूरिज्म का हॉटस्पॉट मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश एडवेंचर टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनके उभरा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और मनभावन वातावरण अनायास ही ट्रेकिंग, सफारी और कैम्पिंग के शौकीनों को आकर्षित करता है। एडवेंचर टूरिज्म की इन्हीं संभावनाओं को

देखते हुए पर्यटन विभाग ने प्रदेशभर में 30 से ज्यादा कैम्पिंग साइट विकसित किए गए हैं। पर्यटकों के हॉलिडे को 'एक्टिव हॉलिडेज' में परिवर्तित करते हुए टूर-डे सतपुड़ा, हेरिटेज रन, पचमढ़ी मॉनसून मैराथन जैसे कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बैलून सफारी, टाइग्रेस ऑन ट्रेल और भोपाल में प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा की स्थापना आदि प्रमुख नवाचार रहे हैं।

वर्तमान में भी मध्यप्रदेश को ३365 डेज का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का संकल्प लेकर सतत प्रयास किये जा रहे हैं। वार्षिक आयोजनों की श्रृंखला में 5

जल महोत्सवों और ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया है। वेब सीरीज पंचायत, गुल्लक और धाकड़ के फिल्मों/कॉम से मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसी दिशा में 'ग्रामीण पर्यटन' की संकल्पना पर वैल्यू फॉर मनी डेस्टिनेशन के विकास कार्य में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाया जाएगा। इससे क्षेत्र विशेष की संस्कृति और धरोहर से पर्यटक परिचित हो सकेंगे।

वैलनेस एंड माइंडफुल टूरिज्म

मध्यप्रदेश को श्वैलनेस एंड माइंडफुल टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी निरंतर प्रयास जारी है। इसमें

पर्यटकों को पर्यटन के साथ योग, ध्यान और नेचुरोपैथी आदि से जोड़ा जाएगा। साथ ही आस-पास टूरिज्म की अवधारणा पर पड़ोसी राज्य के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए छोटी अवधि के टूर प्लान बनाए गए हैं। इससे पर्यटक अपने वीकेंड का प्लान मध्यप्रदेश में कर सकेंगे। इन छोटे-छोटे टूरिस्ट पैकेज से मध्यप्रदेश में पर्यटकों का निरंतर आवागमन भी बना रहेगा और इस आवागमन से आस-पास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी।

पर्यटन-संस्कृति का बेजोड़ संगम और मध्यप्रदेश

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उपजे अवसाद और तनाव के समय में प्रदेश वासियों को राहत देते हुए इस साल पर्यटन विभाग ने उत्सवों का आयोजन किया। इन उत्सवों में पर्यटन और संस्कृति का बेजोड़ संगम देखने को मिला। पर्यटकों ने न सिर्फ स्थान विशेष के नैसर्गिक सौंदर्य को निहारना बल्कि क्षेत्र विशेष की स्थानीय संस्कृति और खान-पान से भी परिचित हुए। नव वर्ष के

शुभारंभ के साथ ही मशहूर प्राचीन शहर मांडू में 13-15 फरवरी को मांडू फेस्टिवल और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 20-26 फरवरी 2021 तक 47वां खजुराहो नृत्य समारोह किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केन्द्रित देश का शीर्षस्थ समारोह खजुराहो नृत्य समारोह राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इसमें देश एवं विश्व के विख्यात कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियाँ देते हैं।

इसी तरह प्राचीन शहर मांडू में मांडू फेस्टिवल के दौरान ऐतिहासिक शहर के अनेक रोचक पहलू से पर्यटकों को अवगत कराया गया। उत्सव के दौरान कबीर केफे, मुक्ति म्यूजिक बैंड और स्थानीय कलाकारों ने अपनी मन मोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। विगत महीने में आयोजित कार्यक्रम में प्रातः कालीन योग सत्र, हेरिटेज वॉक्स, साइकिलिंग टूर, स्टोरी टेलिंग, ट्रेजर हंट, फोटो प्रतियोगिता जैसी रोचक गतिविधियों में हिस्सा लेने के साथ स्थानीय संस्कृति,

कला और स्थानीय व्यंजनों के स्वाद से भी पर्यटक परिचित हुए।

प्रयास यह है कि पर्यटकों को कोई असुविधा नहीं हो और वे मध्यप्रदेश से अविस्मरणीय अनुभवों को अपने साथ ले जाए।

प्रदेश की संस्कृति

प्रदेश की संस्कृति भी पर्यटन का प्रमुख आधार है। पर्यटन के साथ-साथ क्षेत्र विशेष की संस्कृति, धरोहरों, परंपराओं, रीति-रिवाजों और खान-पान से भी पर्यटकों को अवगत कराया जा रहा है।

मध्य प्रदेश ने न केवल अपने प्राचीन सुंदर रूप को सालों पहले सा बनाए रखा है, बल्कि इस समय के यात्रियों के लिए भी यह एक लुभावना गंतव्य है। पहाड़, जंगल, नदियाँ, समृद्ध विरासत, रोमांचक वन्य-जीवन और सांस्कृतिक विविधता से सजी मध्यप्रदेश की प्राकृतिक रचना, इसे वैभवशाली भूमि बनाती है।

इस गौरवशाली अद्भुत धरोहर और संस्कृति को सहेजने और पर्यटकों के लिए सुलभ बनाने के लिए स्थानीय पर्यटन विभाग सतत प्रयासरत रहा है।



कोरोना की आंधी में दूटे कई सितारे

इस आपदा की गहन रात से कई सितारे लड़ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो इस कालिमा में गुम भी हो गए। हम सब जमीन वाले उस आसमान वाले से यही पूछ रहे हैं कि सबेरा कहाँ है? और, कब आयेगा?

मंचदूत डेस्क

आम आदमी ही नहीं खास आदमी को भी अपने मौत के साए में जीने को मजबूर कर दिया कोरोना वायरस जमीन के लोगों को तो मार ही रहा है लेकिन आसमान के सितारों को भी नहीं बख्शा रहा। आम मजदूर तो कोरोना से मर ही रहे हैं खास फिल्मी हस्तियां भी कोरोना की वजह से जान गवां रही हैं।

सैकड़ों नेताओं की जान ले चुका देश-विदेश तक फैल चुका कोरोना वायरस तमाम फेमस पर्सनालिटी को भी संक्रमित कर चुका है। इस समय अमेरिका, जर्मनी, लंदन, इटली, तुर्की, पाकिस्तान व स्पेन तक के विकास गति को रोकने वाला कोविड-19 विगत दिनों बॉलीवुड के फिल्मी सितारों में भी बुरी तरह फैला हुआ था। बॉलीवुड के जिन फिल्मी सितारों को कोरोना काउंट हुआ है उनमें कनिका कपूर, चैन्नई एक्सप्रेस के

प्रोड्यूसर करीम मोरानी की दोनों बेटियों के साथ अभिनेता पूरब कोहली तक संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना का बॉलीवुड में भय इतना हो गया है कि अनेक फिल्में बननी भी बंद हो गई हैं। सभी फिल्मी सितारे आम लोगों से भी यह निवेदन करने लगे हैं कि वह भी अपने घरों में बंद रहें। आधे से अधिक फिल्मी स्टार्स अपने घरों में बंद रह रहे हैं। पिछले साल ही सूचना मिली थी कि पूरब कोहली का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया था। वह कई महत्वपूर्ण फिल्मों में भी काम कर चुके थे। पिछले साल मिली सूचना से व सोशल मीडिया से बात फैली थी कि भारतीय मूल की अभिनेत्री इंदिरा वर्मा भी कोरोनावायरस से संक्रमित हो गई थीं। वह कामसूत्रा जैसी फिल्मों में भी दिखाई थीं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर सभी को

इसकी जानकारी दी। एक बार तो यहां तक शोर मचा था कि अमिताभ बच्चन भी कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। हालांकि अनेक बॉलीवुड सितारे बहुत सुरक्षित जीते हैं लेकिन उसके बाद भी कोरोना उन तक पहुंच जा रहा है। ऐसे में आम आदमी के जीवन की रक्षा करना कितना जरूरी है। सतर्कता ही इससे बचाव व इसका इलाज दोनों है।

अभी पिछले दिनों ही बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मेजर विक्रमजीत कंवरपाल की जिंदगी भी कोरोना ने छीन ली है। वह अपने फिल्मी करियर के लिए याद किए जाते रहेंगे। सूचना के मुताबिक रणबीर कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। उनका इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं आलिया भट्ट, अक्षय कुमार और गोविंदा जैसे अभिनेता भी कोरोना से

संक्रमित हो चुके हैं। बॉलीवुड और उससे जुड़े टीवी फिल्म इंडस्ट्री के भी कई सितारे कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। रितिक भौमिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने को कोरोनावायरस से संक्रमित होने की खबर दी थी। रूपाली गांगुली, नारायण शास्त्री, अबरार काजी, प्रेम सोनी जैसे सितारे भी संक्रमित हैं। फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रेम सोनी कोरोना से पॉजिटिव होने की जानकारी अपने सोशल मीडिया की एक पोस्ट से दिए थे। कंगना रानौत को भी कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया था। इस आपदा की गहन रात से कई सितारे लड़ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो इस कालिमा में गुम भी हो गए। हम सब जमीन वाले उस आसमान वाले से यही पूछ रहे हैं कि सबेरा कहाँ है? और, कब आयेगा?

Since : 2017

LADO INDIA

Customer Help line-
+91 6388637164

हर भारतीय की पसंद!
गुणवत्ता के साथ आर्गेनिक उत्पाद
सभी उत्पाद थोक और फुटकर मूल्य पर उपलब्ध

हमारे प्रमुख उत्पाद
हर्बल और काली चाय, सभी प्रकार के मसाले, मशरूम से बना चयनप्राश और अनेक आर्गेनिक एवं स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद

Registered Office : 73K, Basuchak, Saidpur, Ghazipur, Pin-233306
website- www.ladoindia.in // E- Mail- ladoindia32@gmail.com

Kajaria

Transform your world

“गुणवत्ता”
बड़ी चीज है।



संचालक
संतोष गुप्ता
संजय गुप्ता

Showroom of Tiles

Darshn Marble

Chhota lalpur, Pandeypur, Varanasi, UP

HOUSE OF TILES

Narayanpur, Bhojubar, Varanasi, UP

Help Line- Narayanpur, Bhojubar,

8299611409

Help Line- Pandeypur

8874444495

बहरहाल

फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न

फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं वरिष्ठ लेखक सलिल सरोज

लेखक

भारतीय संसद की लोकसभा में कार्यकारी अधिकारी हैं।



जूनियर कलाकारों ने फिल्म के पदानुक्रम के अंत में बहुत कम सोदेबाजी की शक्ति और केवल दैनिक मजदूरी अर्जित करने के साथ 'एक्सट्रा' के रूप में उन्होंने भयावह सच का सामना किया है। सवाल यह है कि क्या आप समायोजित करने के लिए तैयार हैं? - क्या एक महिला के रूप में, एक जूनियर कलाकार अवसरों के बदले यौन एहसान प्रदान करने के लिए तैयार है? जैसा कि एक पदानुक्रम पर चढ़ता है। महिलाओं द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति भी बदल जाती है।

फिल्म उद्योग में बड़े पैमाने पर यौन हिंसा ने उस समय सार्वजनिक रूप से ध्यान आकर्षित किया जब एक प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता द्वारा 2017 में अपने सहयोगी महिला कलाकार के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। चलती गाड़ी में उसका अपहरण कर लिया गया था और मारपीट की गई। हमलावरों द्वारा

वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। इस मामले में लोकप्रिय अभिनेता -निर्माता, दिलीप को गिरफ्तार किया गया था, और इसने महिला कलेक्टर्स ऑफ सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) में ऑनलाइन दुर्व्यवहार के सदस्यों को निशाना बनाया, जो पीड़िता के समर्थन में सामने आए थे और उद्योग में कुप्रथाओं पर चर्चा शुरू की थी। दिलीप का मुकदमा पूरा होने वाला है और बच्चे को फंसले का इंतजार है। यह इस संदर्भ में है कि फिल्म उद्योग में महिलाओं के लिए काम की शर्तों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो यौन हिंसा और गलतफहमी के माहौल को सक्षम बनाता है।

यूनियनों ने उद्योग की प्रथाओं और मानदंडों को नियंत्रित किया है। हालांकि महिलाओं को इस स्थान पर बड़े पैमाने पर दोषी और अकुशल दिखाया गया है। 'स्क्रिन के पीछे' भूमिका मुख्य रूप से महिलाएँ, पुरुषों द्वारा नियंत्रित की जाती है,

जो प्रवेश स्तर पर ही महिलाओं के लिए बाधाएं पैदा करते हैं। यूनियनों ने जानबूझकर महिला कर्मियों की सदस्यता के लिए कुछ स्पष्ट प्रतिबंधों के अलावा प्रक्रिया में देरी की है, उदाहरण के लिए मेकअप कलाकारों जैसे कुछ व्यवसायों में महिला सदस्यता पर सामूहिक प्रतिबंध।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए अस्तित्व में आया, जो यौन उत्पीड़न से मुक्त कराने के स्पष्ट इरादे से लाया गया था। अधिनियम प्रत्येक कार्यस्थल में दस से अधिक कर्मचारियों की एक समिति के गठन को अनिवार्य करता है, जो यौन उत्पीड़न के किसी भी कथित मामले पर कार्यवाई करने के लिए हैं। इस कानून के अनुसार, यौन उत्पीड़न को अवांछित कार्य या व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है

जैसे (अ) शारीरिक संपर्क और सीमा उल्लंघन य (आ) यौन एहसान की माँग या अनुरोध (इ) यौन रूप से रंगीन टिप्पणी (ई) कोई पोर्नोग्राफी दिखाना या (अ) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक, गैर-मौखिक आचरण। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न समिति की अनुपस्थिति में, अधिनियम इस अधिनियम के तहत गठित स्थानीय शिकायत समितियों से संपर्क करने के लिए उत्तेजित महिलाओं को भी निर्देशित करता है।

देश भर में, फिल्म उद्योग की संरचना इतनी अनौपचारिक है कि एक कार्यस्थल का गठन खुद अस्पष्ट है। जैसा कि उद्योग के विशेषज्ञ टिप्पणी करते हैं कि काम एक निरूपण पढ़ रहा होता है, जब एक पोशाक डिजाइनर खरीदारी कर रहा होता है और जब एक जूनियर कलाकार खेल के मैदान



में इंतजार कर रहा होता है। भले ही उत्पीड़न विरोधी समिति का गठन कुछ संगठित कार्यक्षेत्रों (उदाहरण के लिए, एक प्रोडक्शन हाउस) में होने की संभावना है, एक कार्यस्थल में किसी व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्यवाई का मतलब ज्यादा नहीं होगा, जो लचीलेपन और कार्य संबंधों की अनौपचारिकता को देखते हुए। अपराधी नियत प्रक्रिया से बच सकते हैं और कहीं भी रोजगार पा सकते हैं। उत्तरजीवी को विभिन्न परियोजनाओं में अपराधी के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है या अवसर पर छोड़े

दने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

अपने स्वभाव से, सिनेमा उत्पादन का भौतिक स्थान निश्चित नहीं है। फिल्म की शूटिंग का स्थान दुनिया में कहीं भी हो सकता है। आंतरिक शिकायत समितियों की अनुपस्थिति में, अधिनियम जिला-आधारित स्थानीय शिकायत समितियों में शिकायत का एक विकल्प प्रदान करता है। सिनेमा के काम की गतिशीलता महिलाओं को इस विकल्प तक पहुँचने से भी रोकती है। जबकि काम मोबाइल है, आंतरिक

समितियों का अधिकार क्षेत्र संबंधित जिले तक सीमित है। आदर्श स्थिति में भी, यदि कोई स्थानीय समिति में शिकायत करने का विकल्प चुनता है, तो अधिनियम यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि किसी व्यक्ति को उस स्थान पर शिकायत करनी चाहिए। जहां घटना हुई थी या जहां शिकायतकर्ता निवास कर रहा है।

इसके अलावा, अधिनियम कहता है कि नियोक्ता का कर्तव्य है कि वे उन लोगों से सुरक्षा प्रदान करें, जो महिलाएं कार्यस्थल पर संपर्क में आती हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सिनेमा क्षेत्र में कार्यस्थल कोई भी स्थान हो सकता है। एक उद्योग में जहां सितारे करोड़ों की कमाई करते हैं।

गैर-अनुपालन का परिणाम—जैसे कानून द्वारा 50,000 रुपये का जुर्माना अनिवार्य है अगर कोई नियोक्ता एक आंतरिक समिति गठित करने में विफल रहता है एक फिल्म की उत्पादन लागत की तुलना में तुच्छ है। ये हालात और काम की परिस्थितियाँ उद्योग को अधिनियम के साथ डिजाइन द्वारा असंगत बनाते हैं। जुलाई 2017 में, न्यायमूर्ति के. हेमा की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने डब्ल्यूसीसी से उन शर्तों की जांच करने की मांग की, जो फिल्म

उद्योग में यौन उत्पीड़न को सक्षम बनाती हैं। डब्ल्यूसीसी ने उद्योग को संचालित करने के लिए प्रणालियों पर सिफारिशें मांगी थीं, इसकी खासियत को देखते हुए। आयोग ने एक लंबी और विस्तृत जांच के बाद दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। एक आरटीआई द्वारा रिपोर्ट की प्रति मांगने के एवज में इस कारण का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया कि इसमें व्यक्तिगत आख्यान हैं। व्यक्तिगत विवरण को वापस लेने के बाद एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया गया था।

एक आपराधिक न्याय प्रणाली जो सबूत के बोझ पर बहुत अधिक निर्भर करती है और जिसे लंबी परीक्षाओं की विशेषता है, महिलाओं को न्याय के लिए बहुत उम्मीद नहीं देती है। खसकर उनको जो यौन उत्पीड़न या हमले का सामना करती हैं। हालांकि, यह एक लोकतांत्रिक राज्य की जिम्मेदारी है कि वह हेमा आयोग की रिपोर्ट को जारी करे और महिलाओं को न्याय देने के लिए एक चर्चा शुरू करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में अपनी सिफारिशें रखे, जिन्हें कम से कम एक ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता है जो न्याय की उम्मीद बढ़ाती है।

(लेखक भारतीय संसद में कार्यकारी अधिकारी हैं।)